



B/1682

# भारत का गज़त

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—पार्ट 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]  
No. 33]

नई दिल्ली, भृहस्पतिवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUNA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संख्याएँ के क्षेत्र में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(आधिक कार्य विभाग)  
(बजट प्रसार)  
बजट 1984-85  
(भाग क)

वित्तमंत्री का दिनांक 29 फरवरी, 1984 का भावण

सं. एफ० 15(1)-बी०(डी)/84 :—मेरे वर्ष 1984-85 का बजट  
प्रस्तुत करते के लिए उपस्थित दृष्टा हैं।

2. यह बजट राष्ट्रीय धार्य और हावि के लोक में हुए प्रबल मुधार  
और हमारे भूगतान-शेष में हुई उतनी ही प्रभावशाली वृद्धि की पृष्ठभूमि  
में तैयार किया गया है। वो दिन पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई  
“प्रार्थित समीक्षा” में इन तथ्यों और अन्यव्यवस्था की प्रथ्य बातों के बारे  
में विस्तार से चर्चा की गई है। भ्रत में यहां वर्तमान आर्थिक स्थिति की  
समीक्षा संलेप में ही कहांग।

3. जैसा कि सदन को मालूम है, देश को 1979-80 से 1982-83  
की अवधि में वो वर्ष तक गम्भीर सूखे और एक वर्ष तक कमज़ोर भानसून  
की स्थिति से गुज़रना पड़ा। आशालय का उत्पादन जो 1978-79 में  
1,320 लाख मेट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गया था, परवर्ती वर्ष में  
पट कर 1,100 लाख मेट्रिक टन रह गया। 1981-82 में यह कुछ  
बढ़कर 1,330 लाख मेट्रिक टन हो गया, लेकिन भीषण सूखा पड़ने की

बजह से फिर 1982-83 में बटकर 1,280 लाख मेट्रिक टन हो गया।  
चालू वर्ष के दौरान आशालय के उत्पादन में काफी अधिक प्रगति हुई है और  
संभावना है कि हम पिछली कमी को पूरा ही नहीं कर सकें बल्कि पिछले शिवर  
स्तर से भी काफी ऊपर निकल जाएंगे। आपका है कि 1983-84 में आशालय का  
उत्पादन 1,420 लाख मेट्रिक टन के स्तर से भी आगे बढ़ जाएगा। हावि के  
उत्पादन में कुल मिलाकर पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा सम्भवतः 9 प्रतिशत की  
वृद्धि होगी। सम्भानित सदस्य सहमत होंगे कि यह हमारी हावि संबंधी कार्य-  
नीति के लीक होने और हमारे किसान याइयों की कड़ी मेहनत का प्रबल  
प्रमाण है।

4. श्रीशोगिक लोक के कार्य-निष्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है,  
लेकिन श्रीशोगिक उत्पादन में वृद्धि की गति अब भी छोटी प्रतीत होती है।  
चालू वर्ष के दौरान श्रीशोगिक वृद्धि की दर सम्भवतः 4. 5 प्रतिशत के भ्रात्याकाश  
रहेगी। जबकि 1982-83 में यह दर 3. 8 प्रतिशत थी। 1979-80 के बाद  
की जारी वर्ष की अवधि में श्रीशोगिक वृद्धि की श्रापत दर 5 प्रतिशत से थोड़ी  
सी अधिक बढ़ेगी। यह श्रीशोगिक लोक की अमता से काफी नीचे है। यदि  
हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर को छोड़ देता है और  
आगामी वर्षों में अपने बढ़ते हुए अधिक वर्ष को रोजगार भूहिया करता है  
तो हमें श्रीशोगिक लोक में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि की दर का स्तर  
रखना होगा।

5. वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय धार्य में 6 से 7 प्रतिशत के भीषण वृद्धि  
होने की संभावना है। वर्तमान सरकार के ज्ञान-भार सम्भालने के बाद के इन

चार बर्षों में राष्ट्रीय भार्या में वृद्धि की भी सीमा दर संगमन 5, 4 प्रतिशत रही है जो किसी भी पिछली भार्याओंना के पहने चार बर्षों में प्राप्त की गई वृद्धि की दर ऊंची है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति भार्या में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की भी सीमा दर से वृद्धि हुई होगी। यह उपलब्ध अस्त्यन्त प्रतिकूल ग्रन्तराष्ट्रीय अर्थिक बातावरण और भीषण सुन्दरी की पृष्ठभूमि में देखने पर और भी उल्लेखनीय प्रतीत होगी।

6. वर्ष 1981-82 और 1982-83 की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर बहुत ही कम रही । मुद्रास्फीति की वार्षि. दर जो 1979-80 में 21. 4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गई थी, उसे 1980-81 में 16. 7 प्रतिशत पर और उसके बाद 1981-82 के अंत में केवल 2. 4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर ला दिया गया । 1982-83 के अंत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6. 2 प्रतिशत थी जो एक सूखे के वर्ष के लिए ग्रामानान्य रूप से नीती है । सेकंड चालाक वर्ष के दौरान बहुत बढ़िया फसल द्वारा जो आवश्यक, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में तेजी से वृद्धि हुई है । मानसून के आने में शुल्क में देरी हो जाने ... र अर्थव्यवस्था में नकदी-बाजूल्प होने से वर्ष के पहले भाग में कीमतों पर वज्रब पड़ा । फसल की कटाई के बाद, अक्षरी फसल के अनुकूल प्रभावों को कारण ग्रानांश (दालों से भिन्न) की कीमतों में गिरावट आई । फिरु, आनंदिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से कुछ बस्तुओं, जैसे दालों, कलिपय खाद्य तेलों, रबर, चाय और कपास की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाने की वजह से इस गिरावट का असर काफी हद तक कम हो गया । इसके परिणामस्वरूप, कीमतों में आम तौर पर सितम्बर के अन्तिम दिनों में जो भौमसमी गिरावट प्राया करती है वह कमज़ोर रही ।

7. जैमांकि सदम को मालूम है, सरकार ने सुखे के असर को कम से कम करने भीर कीमतों की बढ़ोतारी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। गैंग चीनी, और खाद्य तेलों जैसी संबंधन शील वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अरिए प्रधिक मात्रा में खरीदने, उपलब्ध कराने भीर जारी करने के लिए कार्यराई की गई। बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान नकदी-बहुल्य को समेटने भीर सरकार के व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए। आन्तरिक उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कपास भीर सी.टी.० सी. चाप के नियांत पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आवश्यकानासार भीर भी उपाय किए जाएंगे ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि 1979-80 जैसा पनुभव फिर न हो जबकि कीमतों में 21 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गई थी।

8. यह मैं यह भाताऊंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी भुगतान की स्थिति कैसी रही है। पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में मैंने सर्वतों को 1982-83 में हमारे भुगतान-जेन में हुए सुधार की जानकारी दी थी। मुझे यह कहने हुए प्रसंस्करण का अनुभव ही रहा है कि 1983-84 में इस स्थिति में भी भी आगे सुधार कुशल है। व्यापारिक घाटा, जो 1981-82 में 5,800 करोड़ रुपए का था, बढ़ कर 1982-83 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का रह गया और खाली बैंच में उसके भीर घट जाने की आशा है। अद्युत्य मर्दों के खाले की प्राप्तियों में भी बुद्धि होती रही है और अनिवार्यों को रकमें जमा कराने के लिए जो प्रोस्तान है विए गए थे के बहुत ही सफल रहे हैं। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकामियों को हिसाब में शामिल करते हुए, जाल विसीय वर्ष में 10 फरवरी तक 662 करोड़ रुपए की बढ़ि हड्ड है।

9. वर्ष 1979-80 में हमारे भुगतान-योग की स्थिति में तेजी से गिरावट आने के बाद, हमने उसे नियंत्रण में रखने के लिए जो कार्य-नीति प्रपनाही थी उससे महत्व कायदा तुमा है। हमारे भुगतानों की स्थिति में सुधार को देखते हुए, सरकार ने स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत 1. 1 अरब एस डी प्रारंभ की योग योगी को न लेने का नियन्त्रण किया है। रिसम्बर, 1981 में इन सदन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञान पर चल रही बहस में भाग लेने हुए प्रधान मंत्री ने कहा था :

यह हमें उधार लेने के लिए मजबूर नहीं करता और न ही हम उधार लेंगे जब तक कि उधार लेना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम स्थीकार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो कि हमारी धौषित और संबंध द्वारा स्वीकृत नीति के अनुकूल न हो। यह तो कल्पना-तीन है कि कोई यह सोचे कि हम किसी ऐसी बाहरी ऐंजेंसी से महायता

श्रीकार कर लेंगे जो हमसे ऐसी शर्तें मनवाएँ जो हमारी इन नीतियों के साथ मैले म बाती हों ।

यह बात उस समय भी सच थी और आज भी सच है ।

10. अपने आपको कफांडा समझने वाले कई लोगों ने जो सर्वानाश की भविष्यत्वाणी की थी उसे मूठा सावित करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे समायोजन प्रयत्नों के कलत्वरूप और अधिक मजबूत हो गई है। हमें जिन भयंकर दुष्परिणामों की चेतावनी थी गई थी उनमें से कोई भी दुष्परिणाम परिट नहीं हुआ। हमने आर्थिक सहायता (सम्बिंदी) में कोई कटौती नहीं की है। हमने किसी का बेतन कम नहीं किया है। हमने आयोजना के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हम अपने संकट में भी नहीं फें हैं। हम गरीबी और करने के कार्यक्रमों प्रबन्धा अपनी जनता की भलाई से संबंधित अपने वकनों से भी विमुख नहीं हुए हैं। हम भलीभांति सोच-समझ कर इस अग्रणी व्यवस्था में शामिल हुए थे और अब हम शान के साथ इस अवस्था से बाहर आ गए हैं।

11. हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज्ञान व्यवस्था के प्रतीक्षित उपलब्ध शेष राशि को न लेने के हमारे निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, कुछ हद तक, अन्य विकासशील देशों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में महायाना देने में मदद मिलेगी। यह सराहनीय है कि विस्तारित कोष सुविधा प्रबन्ध का सम्पूर्ण प्रधानी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ हमारे संबंध सद्भव भौतिक सौहार्दवर्धन रहे हैं।

12 तथापि, प्रातिसंतुष्ट हो कर बैठ जाने की कोई गुणालय नहीं है। हमें उन नीतियों को प्राप्त भी जारी रखना होगा जिनके ये अनुकूल परिणाम निकलने हैं। प्रातिमहस्यपूर्ण क्षेत्रों में आयातों में बचत करने के लिए और नियर्यातों में बृद्धि करने के लिए और भी कठिन परिणाम करने की ज़रूरत है। तेन को छोड़ कर हमारे बाकी नियर्यातों में, 1983-84 के पहले सात महीनों के दौरान 9.9 प्रतिशत बृद्धि हुई है। पिछले कुछ समय से विश्व व्यापार में चल रहे गतिरोध को देखते हुए, यह एक काफी अच्छी प्रगति कही जा सकती है। बृद्धिसील धर्य-व्यवस्था की आयात संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और वृण्ण परियोग्यता अनुपात को प्रबंधयोग्य स्तर पर रखने के लिए हमें हमसे भी बिल्डिंग काम करने की ज़रूरत होगी।

13. सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए साधन जुटाने के हेतु ग्रीष्म प्रायोजन का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक बचतों की दर में बुद्धि करने के लिए पिछले चार वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कर की वरों के समायोजन के अलावा, विनियोग परिसम्पत्तियों के रूप में बचतों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भी राजकोषीय साधन का इस्तेमाल किया गया है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जमा-राशियों पर व्याज की दरों में बुद्धिकारी संशोधन किए गए। ये नीतियां बहुत ही सफल सिद्ध हुई हैं, ग्रीष्म अप्त्य बचतों तथा साविधिक जमा के रूप में धनराशियों की प्राप्ति आशा से अधिक हुई है। आगे बातें वर्षों में राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण काम यह होगा कि वह इस प्रवृत्ति को ग्रीष्म बढ़ावा दे।

14. साधन जुटाने की अपनी कार्य-नीति पर चिकार करते हुए हमें मद्दत्यकार करना होगा कि हमारे कर्त्ता की दरें अपेक्षाकृत ऊंची हैं, लेकिन कर का आधार छोटा है। कासे धन और कर-अपवर्चन की बुराइयों से भी निपटना होगा। सरकार कर-अपवर्चनों के साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह बचनबद्ध है। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो, कर प्रणाली अपने आप में कर-अपवर्चन को प्रोत्साहन देने वाला साधन न बन जाए। इसलिए कर प्रणाली को सरल करने और युक्तिसंगत बनाने के कार्य हमारी राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहने चाहिए।

15. केन्द्रीय सरकारी सेवा के उद्यमों को 1982-83 में 618 करोड़ रुपए का निवास लाभ हुआ था। हालांकि सरकारी सेवा के बहुत-से उद्यमों ने 1983-84 में भी लाभ दियाना जारी रखा फिर भी उनका कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर आशादों के अनुरूप नहीं रहा है। लाभकारिका में कमी प्राप्ति का प्रमुख कारण यह था कि इसापात और कोयला जैसे कुछ बेंगों में हानि हुई थी। सरकार ने उनके कार्य-चलान में सुधार करने के लिए कवाम उठाए हैं। हमें यह सुनिश्चित धरना

होगा कि पूँजी का उपयोग प्राधिक कुशलतापूर्वक किया जाए ताकि भविष्य में विस्तार के लिए प्राधिक साधन उपलब्ध हों।

16. अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को पूरा करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार को अद्वृत से उद्धृत एकों की हाथ में लेना पड़ा और नए साधन पूँजी करके उन्हें नालू रखना पड़ा। हालांकि उनमें से कुछ की हालत ठीक हो गई है, मगर अद्वृत तो से एकबार अब भी घटे वें चल रहे हैं। अब समय आ गया है जब कि सरकारी क्षेत्र के लिए एकों के कार्य-नियावान की भली भाँति समीक्षा की जाए ताकि हमारे साधनों पर कम बोझ पड़े। सरकार का ऐसा करने का प्रस्ताव है। प्रार्थित नियमता ही किसी उद्योग को जीवित रखने की प्रमुख कसीटी होनी चाहिए।

17. चालू वर्ष के दौरान बैंकों के पास जमा-राशियों में जो बृद्धि हुई है वह उद्धृत विस्तार के लिए उनकी धनराशियों की जड़तांत्रियों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। प्रत्यावर्ती में, इसके कारण बैंकिंग प्रणाली में कुछ नक्की-बातुल्य उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में, और सरकारी निवेश के लिए कुछ साधनों को जुटाने के उद्देश्य से, यह बांधनीय समझा जाता है कि एक और वित्तीय मोजना चालू की जाए जिसकी विशेषताएं मोटे तौर पर वही होंगी जो बैंकों की लम्बी अवधिकी जमा-रोजगारों की होती हैं। इस योजना के अंतर्गत, जिसे "राष्ट्रीय जमा योजना" कहा जाएगा, कुछ प्रभित्व केन्द्रों से चार साल की परियोजना वाली जमा-राशियों के प्रमाणपत्र खारीबे जा सकेंगे। निवेशकर्ता को इन प्रमाणपत्रों को एक साल बाद भूमाने का विकल्प होगा। यदि ये राशियां चार बर्षों तक जमा रखी जाएंगी तो व्याज की दर 10.5 प्रतिशत होगी और यदि ये राशियां तीन, दो और एक वर्ष के लिए जमा रखेंगी तो इन पर अमान: 10-9 और 7 प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाएगा। इन जमा-राशियों के व्याज पर आय-कर प्रधिनियम की धारा 80(3) के अंतर्गत 10,000 रुपए की पूर्ण सीमा तक कर से कूट प्राप्त होगी। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में 500 करोड़ रुपए की प्रतिवाही दोनों का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि यह एक अल्पकालीन योजना है और इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा अप्रयावधि यदि मोटिक अट्टनाचक्र को देखते हुए आवश्यक हुआ तो इसे पहले समाप्त किया जा सकता है।

18. पिछले साल सरकार हालांकि नियुक्त की गई वित्तीय संस्थाओं संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, "संपरिवर्तनीयता खंड" में करित्वपर परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। संपरियोजनाओं की पूँजीगत लागत और प्रलाभ-संसीकृत क्षेत्र में निवेश की सीमा में कुछ बृद्धियों को दृष्टिगत रखते हुए, संपरिवर्तनीयता खंड से छूट के प्रारम्भिक सोपना को 1 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

19. इसके प्रलाभ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत न आने वाली कम्पनियों के मामले में संपरिवर्तनीयता खंड लागू नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी में सभी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी भारिता 26 प्रतिशत से प्रधिक होगी। किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों अवृद्धि व्यापारिक धरानों के मामले में, 40 प्रतिशत की मौजूदा सीमा लागू रहेगी। "उद्योग-रहित" जिलों में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, इन जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एकों के संबंध में संपरिवर्तनीयता खंड से पूरी तरह छूट मिलेगी। सहायता-प्राप्त कंपनियों के दोहों में नियुक्त किए गए संस्थाओं के नामजद निदेशकों के कार्यवाचालन में भी सुधार किया जा रहा है। इस विषय में और अन्य संबंधित पहलुओं पर विस्तृत मार्गनिर्देश ग्रन्ति से जारी किए जा रहे हैं।

20. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों के प्राधिनिकीकरण के लिए उदारतापूर्वक वित्तीय सुविधाएं देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो योजना है वह हाल में सभी औद्योगिक एकों पर लागू कर दी गई है और इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की राशि व्याज की 12.5 प्रतिशत की रियायतें दर पर दी जा रही हैं। प्राधिनिकीकरण की योजनाओं की वित्तीय लागत को कम करने वें उद्देश्य से मह नियम किया गया है कि 4 करोड़ रुपए तक के अन्तर्गत को लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजनाओं के अंतर्गत व्याज की दर, ग्रामीण सूचना तक, घटा कर 11.5 प्रति

दी जाएगी। कमजोर एकों को इस राशि तक की सहायता इसमें भी नीची, यानी 10 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी।

21. सदन को मानूस ही है कि सरकार वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की बांधनीयता पर विचार करती रही है। जैसा कि मैंने नव वर्ष सदन को सूचित किया था, मैंने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार आर्मानित किए थे। उनकी प्रतिक्रिया साम तौर पर अनुकूल थी। राज्य सरकारों से और व्यापार तथा उद्योग के देशों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की कार्यवाधियां निर्धारित करने के लिए, मैं एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियंत्रक-महानेत्रपरीक्षक के प्रतिनिधि और कुछ गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इस समिति से अपनी रिपोर्ट सितंबर, 1984 के प्रत्यंत तक प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

22. अब मैं 1983-84 के मंसोधित अनुमानों और 1984-85 के बजट अनुमानों की ओर आना चाहूँ।

#### 1983-84 के मंसोधित अनुमान

23. सदन को यारू होगा कि 1983-84 का केन्द्रीय बजेत जा आयोजना परिव्यय 13,870 करोड़ रुपए रखा था। इसे 8,390 करोड़ रुपए तक बढ़ाने से और 5,480 करोड़ रुपए तक सरकारी बजेत के उद्यमों के आन्तरिक स्था बजट-मात्रा साधनों से पूरा किया जाना था। सरकारी बजेत के कुछ उद्यमों के आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने के बावजूद, मेरा यही प्रयास रहा है कि वर्ष के दौरान कुल आयोजना परिव्यय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पहुँचे। अब अनुमान है कि 1983-84 में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 14,059 करोड़ रुपए होगा। बजटीय समर्थन में, बजट अनुमानों की अपेक्षा, 1,007 करोड़ रुपए की बृद्धि करके ऐसा करना संभव हुआ है।

24. डाक-तार आयोजना के लिए बजटीय समर्थन की राशि में 203 करोड़ रुपए की बृद्धि की गई है। रेलवे के आयोजना परिव्यय में भी 54 करोड़ रुपए के प्रतिरिक्त बजटीय समर्थन के साथ, 100 करोड़ रुपए की बृद्धि की गई है। परिवहन और संचार बजेत में, मैंने 'इस्टेट' जैसी अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए और दूरवर्षन के व्याप्ति-बजेत का विस्तार करने के लिए अंतरिक्ष धनराशियों की व्यवस्था की है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए, बजट संवर्ध्यस्था में 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रसायनों और उर्वरकों के लिए आवृद्धि राशि में 133 करोड़ रुपए की बृद्धि अधिकांशतः आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने और वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण की गई है। ऊर्जा के बजेत में, नियांद्रीन परियोजनाओं के कार्य की गति को तेज करने के लिए कोयला संबंधी परियोजनाओं को 30 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष धनराशि दी गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूँजी आधार को सुधूकरने के लिए 130 करोड़ रुपए की एक विशेष व्यवस्था की गई है। आलू वर्ष में प्रारम्भ किए गए नए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े बच्चों के कल्याण के लिए भारत स्वास्थ्य स्था परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक बजेतों के लिए भी व्यवस्था में बृद्धि की है।

25. राज्यों और संघ राज्य बजेतों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 392 करोड़ रुपए की बृद्धि करके उसे 4,462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,854 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें उन राज्यों को आयित रुप से भी गई आयोजना सहायता की 190 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो विशेष रूप से आलू वर्ष की पहली छान्ही में मानसून न आने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। आसाम राज्य को 82 करोड़ रुपए की अंतिरिक्ष आयोजना सहायता दी गई है, जिसका अधिकांश भाग उस राज्य में दंगों से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वस्था की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है।

26. आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखने के लिए भस्सक सावधानी बरती रही है। किर भी, कुछ अपरिहार्य व्यवस्थाएँ बदलना पड़े। राज्यों की विए जाने पर्याप्त अधिकारों के लिए श्रीराजपाल-व्यापार करारों के अंतर्गत तकनीकी अधिकारों के लिए 400 करोड़ रुपए की अंतिरिक्ष व्यवस्था की गई है। कृषि संबंधी निविष्टियों (इनपुट) के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अन्यावधिक व्ययों में

110 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। राज्यों को लिए जाने वाले जग्हनों में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि ग्रल्प बचतों की राशि भविक मात्रा में एकल होने के कारण इन बचतों में उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कोई 15 राज्यों में बातें और चक्रवातीय तूफान आए तथा आपोजनावृष्टि हुई। इन विपरियों के कारण दीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए के भवित्वित आपोजना-भिन्न अनुमान की व्यवस्था की गई है।

27. इसके भवित्वित, मैं राज्यों को 500 करोड़ रुपए की भवित्वित आपोजना-भिन्न सहायता देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। इस विषय में मैं बाद में राज्यों के ग्रामीण वर्ष के आपोजना परिवर्त्य पर विवार करते समय चर्चा करूँगा। 500 करोड़ रुपए के इस जग्हन में से 400 करोड़ रुपए की राशि से राज्यों को भपने 1982-83 के बाटे साफ करने में सहायता मिलेगी।

28. रक्षा के लिए व्यवस्था को 5,971 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित अनुमानों में 6,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वर्ष में, सरकारी कर्मचारियों के लिए भंजूर की गई अन्तर्रिम राहत और बोनस के कारण सरकार के कार्यालयों के संबंध में लगभग 280 करोड़ रुपए की वर्चा आने का अनुमान है। आपोजन और स्वदेशी उर्जाकरों पर दी जाने वाली भार्यक सहायता की राशि 250 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1,048 करोड़ रुपए की हो जाएगी क्योंकि जून 1983 में उर्जाकरों की उपचारता कीमतों में कमी कर दी गई थी। चालू वर्ष के दीरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सरकारी लेन के कुछ उद्यमों को, आसदौर से ही इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राष्ट्रीय बस्त निगम और विल्ली परिवहन निगम को, बजट में की गई व्यवस्था से विभिन्न आपोजना-भिन्न सहायता की जल्दत पहुंची। इसके प्रलापा कलकाता पत्तन और हालिया बैमल के तलकर्वण (ड्रेजिंग) के लिए भार्यक सहायता की योजना को ग्रामीण वर्ष के अंत बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

29. संशोधित अनुमानों में, भंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भपने बड़े हुए कोटे के संबंध में भवित्वान देने के लिए, 502 करोड़ रुपए की भवित्वित व्यवस्था भी आगित की गई है। किन्तु, इसका बजट पर कोई निवल प्रभाव नहीं पहुंचा क्योंकि कोटे के भवित्वानों के लिए की जाने वाली भार्यायगिया तबमुल्प प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित हो जाती है। उपर्युक्त और अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर, संशोधित अनुमानों में आपोजना-भिन्न व्यय की राशि 24,773 करोड़ रुपए रखी गई है जबकि बजट अनुमानों में इसकी राशि 21,984 करोड़ रुपए की थी।

30. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है, आय-कर और सीमा-गल्कों की प्राप्तियों के बजट अनुमान संभवतः पूरे हो जाएगे। निगम-कर की प्राप्तियों में, लेन कंपनियों द्वारा भविक भार्यायगिया किए जाने के कारण 203 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। संष-उत्पाद-गुल्कों में भी, कम्पने तेस (कूड़) और कोयले पर उपकरों की अविक राशि प्राप्त होने के कारण 85 करोड़ रुपये की भविक प्राप्ति होने का अनुमान है। केन्द्र का कर-राजसव, करों में राज्यों के हिस्सा भवा कर दिए जाने के बाद, 15,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 15,460 करोड़ रुपए का था।

31. कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत, रेलवे के लाभांश के रूप में, बजट अनुमानों की घोषका 127 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है किन्तु यह कभी व्यय की अंतर्गत वृद्धियां हो जाने से भवित्वितसंतुलित हो जाएंगी, और चालू वर्ष में कर-भिन्न राजस्वों की कुल राशि, बजट अनुमानों की घोषका 130 करोड़ रुपए भविक होने की आसा है।

32. मुझे सबन को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पूँजी खाते की प्राप्तियों के अंतर्गत, चालू वर्ष के दौरान ग्रल्प बचतों के निवल संग्रह की राशि 2,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि बजट अनुमान 1,700 करोड़ रुपए का था। यह चालू वर्ष के बजट में ग्रल्प बचतों के लिए लिए गए प्रोत्साहनों का स्वागत-न्यौग्य गुपरियांग है। आसा है, तकनीकी ग्रहणों की बापसी भार्यायगी से 1,150 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जबकि बजट में 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। व्यय को घटाने के बाद निवल प्राप्ति की राशि, बजट अनुमानों के 200 करोड़ रुपए के नुकाबने, 350 करोड़ रुपए होगी।

33. गैर-सरकारी भवित्वित विधियों की विशेष जमाराशियों और ऐसी ही अन्य रकमों से बजट अनुमानों की घोषका 190 करोड़ रुपए भवित्वित प्राप्त होने का अनुमान है। तेल क्षेत्र की विशेष धनराशियों की जमा रकमों, राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोंपाय और ग्रल्पविकारिक विधियों की अतिरिक्त वसूलियों और अन्य घट-बद्ध को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष में पूँजी खाते की प्राप्तियों 15,965 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में इनकी राशि 12,656 करोड़ रुपए दिखाई गई थी।

34. इस प्रकार कुल प्राप्तियों की राशि 33,250 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,929 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इससे चालू वर्ष में बजटीय बाटा 1,695 करोड़ रुपए का रहेगा, जबकि बजट अनुमानों में 1,586 करोड़ रुपए का बाटा दिखाया गया था। इस राशि में 400 करोड़ रुपए की वह विशेष जग्हन सहायता की राशि शामिल नहीं है जो पूर्ववर्ती वर्ष 1982-83 के अंत के आवारद्रूपट साफ करने के लिए राज्यों की दी गई थी। सबन प्रबल्य ही मुझ से सहमत होगा कि अपरिहार्य बजटीय विवादों के बावजूद, हम बाटे को विवेकपूर्ण सीमाओं में रख सके हैं।

#### 1984-85 के बजट का अनुमान

35. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जब हमारी सरकार ने जनवरी 1980 में शासन-भार संभाला था, उस समय हमारे सामने एक ग्रल्पविकारिक कार्य यह था कि आपोजन की प्रक्रिया को पुनरुज्जीवित किया जाए और विकास के कार्यक्रमों को नवा बल प्रदान किया जाए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मिले चार सालों में, हम सार्वजनिक निवेश की गति में अस्तूपूर्व वृद्धि कर सके हैं।

36. वर्ष 1984-85 के लिए, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अनुमोदित आपोजना परिवर्त्य 30,132 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983-84 में इसकी राशि 25,480 करोड़ रुपए की थी। 1984-85 के लिए केन्द्रीय आपोजना परिवर्त्य की राशि 17,351 करोड़ रुपए रखी गई है, जो कि 1983-84 के 13,870 करोड़ रुपए के अनुमोदित आपोजना परिवर्त्य से 25 प्रतिशत भवित्वित है।

37. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपोजना परिवर्त्य की राशि 12,781 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि 1983-84 में भवित्वित परिवर्त्य की राशि 11,678 करोड़ रुपए की थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आपोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 3,050 करोड़ रुपए की होगी, जबकि 1983-84 के बजट अनुमानों में यह राशि 4,462 करोड़ रुपए की थी और इस प्रकार इसमें चालू वर्ष में किए गए आवारद्रूपट की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

38. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपर्युक्त सम्बन्धीय आपोजना परिवर्त्य के अंतर्गत ग्रल्प-ग्रल्प राज्यों की आपोजनाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों ने भपने विवादों का ग्रबन्ध बहुत अच्छी तरह किया है; वे भवित्वित साधन जुटाने में भी उनका पर्याप्त आकार की आपोजनाओं के कार्यालयन में प्रभावोत्पादक उपयोग करने में सफल हुए हैं और इस प्रकार उन्होंने भपने विकास और भपनी जनता की वृद्धि के लिए व्यवस्था की है। बुमियवस्था, कुछ राज्यों ने भपने निरी कारणों से, भपने साधनों का इस्तेमाल बहुत-से प्रभ्य प्रयोजनों के लिए किया है; उन्होंने भपने साधनों को, जिनमें जुटाए गए प्रतिरिक्त साधन शामिल हैं, विकास के लिए नहीं लगाया है और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से भी आवारद्रूपट की बड़ी-बड़ी रकमें ले ली है।

39. ऐसे राज्यों को भी सहायता देने के लिए, समय समय पर विभिन्न सुविधाएं और भवसर विए गए थे। छठी आपोजना के शुरू में ही 1,412 करोड़ रुपए की भवित्वित सहायता की बकाया राशि की बहुत-सी व्यापित कर दी गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि राज्य साफ खाते के साथ शुश्मात कर सकें। किन्तु राज्यों के आवारद्रूपट फिर बह गए और भूर जून 1982 में मैंने 1743 करोड़ रुपए के भवित्वित विधियों के लिए इतिशेष बाटे को साफ करने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक से भी राज्यों को दुगना कर दिया। पिछ्ले साल किर, बजट प्रसुत करते समय मैंने केन्द्रीय सहायता के स्तर में वृद्धि करने की घोषणा की। ये सारे उपाय मुक्क्यतः राज्यों को इस बात की सहायता देने के लिए किए गए थे जिनमें विवादों

मामलों का पुलः समायोजन कर सके और पर्याप्त आकार की अपनी आयोजनाओं को क्रियान्वित कर सके।

40. दुर्भाग्य की बात है कि इन उपायों के बावजूद, कुछ राज्यों ने मार्च 1982 के बाद भी ओवरड्रूपटों पर अधिक निर्भर रहना जारी रखा। मार्च 1984 के बात में उनके प्रत्यक्षित थाटों का उनकी आयोजनाओं के आकार पर कठोर प्रभाव पहेंगा, यदि सामान्य परिषदारी के अनुसार, इन थाटों को उनकी अगले वर्ष की आयोजना में समायोजित किया जाएगा। इस समस्या को कावू में रखने के उपायों पर विचार करते समय में अपने ग्रामों की दुर्विधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक और, देश का कोई भी वित्त मंत्री किसी भी राज्य की आयोजना के आकार के विषय में उदासीन नहीं रह सकता। दूसरी ओर, यदि चूकला राज्यों का सहायता दी जाती है तो सुप्रबंधित राज्यों की यह शिकायत उचित होगी कि उन्हें अपने बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र से न्यायोचित पुरस्कार नहीं मिला है।

41. पिछले कुछ सप्ताहों में, उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से फिर विचार-विमर्श किया गया है, जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्रूपट की राशि अनुमति दी गई है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और ओवरड्रूपटों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करें। मैं स्वयं इस बात के लिए सहमत हो गया हूँ कि मैं भी राज्यों को प्रतिरिक्त सहायता देने के लिए और उपाय कलंगा ताकि जहां तक संभव हो राज्यों की आयोजनाओं को बनाया जा सके। ऐसा करने समय में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को तेज रखने की आवश्यकता के प्रति विशेष रूप से सजग रहा हूँ। केंद्रीय सहायता की राशि में भी और बढ़ी जी जा रही है। इसे हिसाब में लेते हुए, आयोजना अवधि में कुल सहायता की राशि आयोजना प्रलेख में परिकल्पित 15,350 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 17,790 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैंने 1983-84 में संशोधित अनुमानों में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अवधि स्थापित की है। इस विशेष सहायता से ये राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अपने ओवरड्रूपट अधिक रूप से साक कर सकेंगे। राज्यों को यह भी बता दिया गया है कि उनके इतिहास थाटों को, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्तीयां यीमानों तक, अगले वर्ष के आयोजना साधनों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

42. उन राज्यों के मामले में जिन्होंने अपने वित्त का अन्तर्गत प्रबन्ध किया था 1984-85 में उनको कुछ अतिरिक्त सहायता देने की एक उपयुक्त योजना बना रखा है। यह न्यायसंगत और समुचित ही है।

43. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सबन मुझसे इस बात के लिए सहमत रहोगा कि अपनी भिजी साधन संबंधी कठिन समस्याओं के बावजूद, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो कुछ भी वह अधिक से अधिक कर सकती थी, किया है। आकी जो कुछ करना है वह उन्हें स्वयं करना है।

44. छठी आयोजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र की आयोजना कुल मिलाकर, चालू कीमतों पर 110,000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। इसकी तुलना में पूर्ववर्षीय पांच वर्षों का आयोजना परिव्यय 46,700 करोड़ रुपए का था हालांकि इन पांच वर्षों में से तीन वर्ष ऐसे हैं जो पिछली सरकार के द्वारा संचालित “गैर-आयोजना” के हैं। बास्तविक रूप में भी, छठी आयोजना का परिव्यय, पिछली किसी भी आयोजना के परिव्यय की तुलना में, बहुत अधिक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह बूझ चालू आयोजना की अवधि में विकास की गति को सेज करने में इस सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का एक मापदण्ड है।

45. पिछले चार सालों में, वर्तमान सरकार ने समाज के कमज़ोर लोगों, विशेष रूप से आमीण क्षेत्रों में रहने वालों के फायदे के लिए बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में एकीकृत आमीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय आमीण रोजगार कार्यक्रम और 15 अगस्त, 1983 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दो नए कार्यक्रम, अर्थात् आमीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना शामिल है। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश लक्ष्यगत विशिष्ट समूहों के लिए आमदानी और रोजगार वे अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक परिस्थितियों का निर्माण करना भी है।

46. अगले वर्ष की आयोजना तैयार करते समय, हमने इन कार्यक्रमों को और ऐसे अन्य कार्यक्रमों की भी जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आमीण निर्भानों को कायदा पहुँचता है, अधिक से अधिक समर्थन दिया है। आमीण विकास भवितव्य के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित कुल राशि 932 करोड़ रुपए भी होगी जो कि 1983-84 में रखी गई 480 करोड़ रुपए की राशि से लगभग दुगुनी है। एकीकृत आमीण विकास कार्यक्रम के लिए 216 करोड़ रुपए की राशि की अवधि स्थापित की जा रही है; उतनी ही राशि राज्यों द्वारा भी दी जाएगी। 1984-85 में इस कार्यक्रम के सामानुभवित विद्युतीयों की संख्या अनुमान: 30 लाख से अधिक होगी। राष्ट्रीय आमीण रोजगार कार्यक्रम के लिए, 1984-85 के संबंध में 230 करोड़ रुपए के परिव्यय की अवधि की गई है; इस कार्यक्रम के लिए भी इतनी ही राशि की अवधि स्थापित की जाएगी।

47. आमीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आमीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की परिकल्पना की गई है, के लिए आवंटित राशि को, 1983-84 के 100 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1984-85 में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से और राष्ट्रीय आमीण रोजगार कार्यक्रम से कुल मिलाकर, 1984-85 में आमीण क्षेत्रों में 55 करोड़ कार्य-विवरसों (मैन डेज) के रोजगार की अवधि स्थापित होगी। शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि की अवधि स्थापित की जा रही है। जैसा कि सबसे मालूम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई बजट अवधि का उपयोग वैकों द्वारा दिए जाने वाले व्यव्योगों के एवज में पूर्जीत आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा। मैं यह बताता दूँ कि इन दो सए कार्यक्रमों के लिए, अवधि की जाएगी।

48. वर्ष 1984-85 की आयोजना में, टैक्सिंग आमीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए 243 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि अनुनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए 364 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित करेंगे। 1984-85 के दौरान 50,000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों की पीड़ि के पासी की भुविधाएं मुहैया किए जाने की आशा है।

49. एकीकृत बाल विकास सेवाओं का कार्यक्रम हमारे उन प्रयत्नों का एक भवित्वपूर्ण अंग है जिनसे हम अपने देश के पिछड़े इलाकों, शहरी गंदी बरितों और जनजातीय शेत्रों में मिलाओं और बच्चों को मदद देना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 820 खंडों में पहले से ही जल रहा है। 1984 के अंत तक, यह योजना सभी 1000 निर्धारित खंडों में पूरी तरह चालू हो जाएगी। इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित की गई है। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए, 1984-85 में कुल मिलाकर 78 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित की जा रही है।

50. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों स्वाय अवधि विकास के लिए केवल 176 करोड़ रुपए की तुलना में, 1984-85 में 209 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित की जा रही है। विकास और संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय की, जो 1983-84 में 155 करोड़ रुपए का था आधा, आपसी अधिक बढ़ाकर 1984-85 में 204 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इनी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ी की गई है; इसके लिए 1983-84 में 460 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित की जा रही है, अब 1984-85 में 605 करोड़ रुपए की अवधि स्थापित की जा रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 करोड़ सोना और आ जाएगे।

51. सरकार की उपर्युक्त और अन्य सामाजिक-आर्थिक प्रायमिकताएं 20-सूत्री कार्यक्रम में परिलक्षित होती हैं, जिसे ओवरार बरोके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए केवल 15 आयोजना में बहुत-सी योजनाओं और विभिन्न आयोजनाओं को नियुक्ति रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना शामिल है। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश लक्ष्यगत विशिष्ट समूहों के लिए आमदानी और रोजगार वे अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक परिस्थितियों का निर्माण करना भी है।

हुए, 20-पूरी कार्यक्रम के लिए कुल व्यवस्था 11,858 करोड़ रुपए की होगी, जो केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य भेवां के कुल कार्यक्रम आयोजना परिवर्तन के सामग्र 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

52. छवि के भेवां में जो अवधारण प्रगति हुई है वह अपेक्षवस्था के लिए सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस भेवा के विकास को बर्तमान सरकार द्वारा दी गई उच्च प्रायमिकता अगले वर्ष की आयोजना में भी जारी रखेगी। इस प्रकार, छवि भवनालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल परिवर्तन की राशि, चालू वित्तीय वर्ष के 556 करोड़ रुपए की तुलना में, 758 करोड़ रुपए की होगी। इस परिवर्तन में राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए की राशि शामिल है; इस परियोजना में भी और पहले से चले आ रहे अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 1984-85 में ही 9.4 लाख मेट्रिक टन के अनियक्ष उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

53. देश के आधारभूत डांबों को और मजबूत करने के लिए विष्युत, कोयला, रेलवे और पत्तों के लिए अधिक योग्यियों की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न विष्युत परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 1,764 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है; जो 1983-84 की तुलना में 44 प्रतिशत वृद्धि की व्यापारिक है। कोयल वित्तीय की परियोजनाओं के लिए 1,310 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1983-84 में 1,076 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी; और 1984-85 में 1,520 लाख मेट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1984-85 में रेलवे के लिए 1,650 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जो कि चालू वर्ष की अपेक्षा 23 प्रतिशत अधिक है। यह अ.शा. की जांती है कि रेलों द्वारा धोना जाने वाला राष्ट्रीय उपर्याक यातायात 1984-85 में बढ़कर 2,450 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। पत्तों के विकास के लिए 201 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मद्रास बंदर-गाह को गहरा करने के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

54. पेट्रोलियम के लिए 3,127 करोड़ रुपए के परिवर्तन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अवैष्णव और उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए 2,685 करोड़ रुपए और तेल योग्यता वित्तीय की विभिन्न योजनाओं के लिए 443 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 1984-85 में सामग्र 300 लाख मेट्रिक टन कल्पे तेल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। एक गैस पाइप-लाइन परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना के द्वारा बिजूपुर, जारीशाहूर, आंबला, बबराला, शाहजहानपुर और सवाई माधोपुर में स्थापित की जाने वाली नई उत्कर्ष परियोजनाओं को बेसिन गैस की सप्लाई की जाएगी।

55. इस्पात, अशोह धारुओं, कागज, सीमेंट और अन्य बहुत से शेवां के लिए, जो देश के आयोगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, पहले से अधिक धनराशयों की व्यवस्था की जा रही है। मैं सदन का ध्यान उन कार्यक्रमों की और भी विलाना चाहता हूँ जो 1984-85 की आयोजना में विज्ञान और ग्रीष्मीयकी, प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दाएँ के लिए शामिल किए गए हैं। पिछले अगस्त में इन्स्टेट-1 वी को भूकेंट्रिक कक्ष में सालातापूर्वक स्थापित करना हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशनों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है। हमारे लिए यह एक गंभीर का बात है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों की ओर से जामिल हो गया है जिन्होंने दक्षिणी वृद्धि प्रदेश में स्थायी वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। भारत ही एक ऐसा विकाससाधन देश है जिसे समूही कानून सम्मेलन से "अग्रणी निरेशक" (पायमिअर इन्वेस्टर) के रूप में मान्यता प्राप्त होने की प्रतिष्ठा मिली है, जिससे हम गहरे समझे हलों के व्यावर्जन साकेनों का उपयोग करने का अधिकार मिल गया है।

56. अंत में, मैं यह बतला देता चाहुंगा कि जुने हुए शेवां में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की योजनाएँ 1983-84 में शुरू की गई थीं, जो 1984-85 में भी जारी रखेंगी। जैसा कि सदन को मालूम है, मैं परियोजना भेवां के योजनालय में सामग्र 40 प्रतिशत के लिए और बड़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए की एकमूल राशि की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि सम्मानित सदस्य मुझे कोई ऐसा जादूर समझ नहीं जो हमने कम साधनों से इतना अधिक कर सकता है। इनमें मैं जल्दी से यह स्पष्ट कर दूँ कि मेरे प्रोत्साहन योजनाएँ विनियोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिवित साधनों की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं। हनमें से प्रत्येक योजना के लिए अलग से भी योज्य माला में धनराशि की गई है।

या सीमावित किसानों के कार्यक्रमों, ग्रामीण जलपूति योजना, भारती गंभीर वित्तीयों में पर्यावरणिक सुधार, कमान और विकास परियोजनाओं के अंतर्गत शेवां में सरणियों का निर्माण, और स्नेहीयों के लिए प्रोड किका और बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और बड़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए की एकमूल राशि की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि सम्मानित सदस्य मुझे कोई ऐसा जादूर समझ नहीं जो हमने कम साधनों से इतना अधिक कर सकता है। इनमें मैं जल्दी से यह स्पष्ट कर दूँ कि मेरे प्रोत्साहन योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिवित साधनों की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं। हनमें से प्रत्येक योजना के लिए अलग से भी योज्य माला में धनराशि की गई है।

57. मैंने 1984-85 की वार्षिक आयोजना के जबैशों और उसकी मुख्य-मुख्य प्रायमिकताओं का बहुत ही संक्षेप में विवेचन किया है। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी ब्रेक-पत्रों में उपलब्ध है।

58. आयोजना के लिए व्यवस्थामंडल अधिक से अधिक परिवर्तन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, मैंने हस्त बात का विशेष ध्यान रखा है कि आयोजना-मिल व्यवस्था निम्नतम स्तर पर रखा जाए। किन्तु कानिपय वृद्धियों करना आवश्यक और अपरिहार्य है। मैं यह भी बतला दूँ कि राज्य सरकारों से होने वाली प्राप्तियों और उनको की जाने वाली अदाय-प्रियों के अनुमान तैयार करने समय, आठवें वित आयोग की अन्तरिम स्पोर्ट्स में भी गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। इस विषय में मैं सदन को पहले सुनित कर चुका हूँ। आयोग की अन्तिम स्पोर्ट्स अंग्रेज, 1984 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

59. मैंने राज व्यवस्था के लिए, इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 6,350 करोड़ रुपए के मुकाबले, आगे वर्ष 6,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मूले विषवास है कि सदन इस बात में मूलसे सहमत होगा कि रक्षा के लिए सभी ज़हरतां को देख की सुरक्षा के हित में पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए। अगले वर्ष व्याज की व्यायायियों की अनुमानित राशि, इस वर्ष के 4,850 करोड़ रुपए के मुकाबले, 5,600 करोड़ रुपए की होगी। उधार की राशियाँ अधिकांशतः हमारे विकास कार्यों का वित्त-पोषण करने के लिए ली जाती हैं और व्याज की व्यायायियों की राशि में वृद्धि बताने की हमारी नीतियों की सफलता के कारण ही है। खाद्य संबंधी आधिक सहायता के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी और आयातित उत्कर्षों पर आधिक सहायता देने के लिए 1,080 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। नियत संवर्धन और विषयान विकास के लिए 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

60. केन्द्रीय सरकार के कार्यवाचियों को महाराई भर्ते की अतिवित किस्त और पैशान राहत आदि देने के लिए 1984-85 में 300 करोड़ रुपए की एकमूल व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं और समायोजन के स्वरूप वाली अन्य व्यवस्थाओं को हिसाब में लेने पर, 1984-85 में कुल आयोजना-मिल परिवर्तन अनुमानतः 26,066 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983-84 के संशोधित अनुमानों में 24,773 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

61. जहाँ तक 1984-85 में प्राप्तियों का संवर्धन है, करावान के बर्तमान स्तरों पर 22,993 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जिसको तुलना में हस्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 20,946 करोड़ रुपए की राशि परिवर्तित की गई है। अनुमान है कि 1984-85 में करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के 3,248 करोड़ रुपए के मुकाबले, 5,739 करोड़ रुपए का होगा और इस प्रकार इसमें सामग्र 500 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार, केंद्र का नियस नर-राजस्व, चालू वर्ष के 15,700 करोड़ रुपए की तुलना में, 17,254 करोड़ रुपए का होगा। रेलवे और डाक-तार से प्राप्त होने वाली लाभांश, 1983-84 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 106 करोड़ रुपए अधिक होगा। सरकारी बेत्र के

उद्यमों और राज्य सरकारों से व्याज की अदायगी और व्याजों की वापसी अदायगी के द्वा में पहले से अधिक राशि प्राप्त होती।

62. बाजार व्याजों से चालू वर्ष के 4,000 करोड़ रुपए के मुकाबले, अगे वर्ष 4,100 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अत्यं बचतों के संग्रह की राशि चालू वर्ष के 2,200 करोड़ रुपए के मुकाबले, 2,400 करोड़ रुपए आकी गई है। बापौरी अदायगी की राशि के घटाने के बाद, निवल विदेशी सहायता की राशि चालू वर्ष के 1,902 करोड़ रुपए जो तुलना में अनुमानित 2,089 करोड़ रुपए की होती। अत्यं वर्ष के बजट में उस राष्ट्रीय जमा योजना से प्राप्त होने वाली 200 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल की गई है जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में पहले किया है। इन प्राप्तियों और प्राप्तियों में होने वाली अन्य घट-बढ़ की दिसाव में लेने के बाद, अनुमान है कि 1984-85 में कुल 40,501 करोड़ रुपए की प्राप्तियाँ होंगी। इन प्राप्तियों में रेलवे के यात्री किराए और माल-भाड़े में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को दिसाव में ले सिया गया है। कुल अनुमानित राशि 42,536 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार बजट में करावान की मौजूदा वर्षों पर कुल मिलाकर 2,035 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

63. मैंने सदन का काफी समय ले लिया है। अब मैं अन्य कर प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

### (भाग ४)

64. इन प्रस्तावों को तैयार करते हुए, मैंने अधिक स्थिति की उन वास्तविकताओं को व्यापार में रखने को कोशिश की है, जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण के शुरू में किया था। मुझे आशा है कि ऐसा करते समय मैंने उस विशिष्ट आगामी घटना को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया है, जिसका संसद के हम सब लोगों के लिए बड़ा भवित्व है।

65. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला प्रस्ताव निगम-भिन्न आय-कर के क्षेत्र के बारे में हूँ। मेरा वैयक्तिक करावान की दरों के समूचे ढांचे में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है। 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक की कर-भूगत्य आय के पहले बंद पर कर की मौजूदा दर 25 प्रतिशत है। सधन को याद होगा कि मिलिये वर्षे इस दर को उम समय विद्यमान 30 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 20,000 रुपए से ऊपर के सभी आय-स्तरों पर भी राहत दी गई है। 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनियों पर कर की अधिकतम सीमातिक दर को 60 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। उदाहरणार्थे, कुछ छंडों पर कर की नई दर इस प्रकार होगी: 25,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के आय-बंद पर नई दर 35 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 30 प्रतिशत, 50,001 रुपए से 60,000 रुपए तक के आय-बंद पर 50 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 45 प्रतिशत, और 70,001 रुपए से 80,000 रुपए तक के आय-बंद पर 55 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 50 प्रतिशत होगी।

66. उक्त प्रस्ताव से आय के भी स्तरों पर राहत मिलेगी। मुझे आशा है कि मानक कटीवी में पिछले वर्ष की गई दृष्टि के साथ-साथ इस उपाय से विशेष रूप से बड़ी आमदनी वाले वर्गों को काफी राहत मिलेगी। संघोधित कर अनुसूची के अनुसार 20,000 रुपए की आय वाले करावानों को कर 281 रुपए की राहत प्राप्त होगी, जो उसके द्वारा पहले देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर है। 30,000 रुपए के आय-स्तर पर यह राहत 844 रुपए अथवा पूरने दरदांबे के अंतर्गत देय कर के 16.67 प्रतिशत के बराबर, और 50,000 रुपए की आमदनी के स्तर पर देय कर के 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

67. अनुमान लगाया गया है कि करावानों की संख्या में और विभिन्न आय-बंदों की निर्धारित आमदनियों में कोई परिवर्तन न होने पर, प्रस्तावित दर अनुसूची से राजस्व में 180 करोड़ रुपए की हानि होगी। लेकिन कर की दरों को कम करने पर सामान्यतः यह आशा की जा सकती है कि इसके कल्पनारूप विभिन्न आय-बंदों पर करावानों की संख्या में

दृष्टि होगी और कर संबंधी उपर्योगों का अपेक्षाकृत अधिक अचली तरह पालन होगा। इन बातों को व्यापार में रखते हुए, मैंने राजस्व में केवल 59, करोड़ रुपए की निवल हानि हीने की परिकल्पना की है। यह हानि पूर्णतः बंदों आय वाले वर्गों को कर में दी गई राहत के परिणामस्वरूप हुई भानी जा सकती है। जहाँ तक व्यापार और व्यवसाय से होने वाली आय का सम्बन्ध है, मेरी यह आशा है कि दरों में कमी किए जाने से कर संबंधी उपर्योगों का अधिक अचली तरह पालन करने और आय को अधिक सही रूप में प्रकट करने को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में होने वाली कमी इससे अंशतः पूरी हो जाएगी।

68. अध्यक्ष महोदय, एक तरह से इस प्रस्ताव से कर प्रणाली को मुक्तिसंगत बनाने के उस कार्यक्रम को जारी रखा गया है, जो मेरी पार्टी द्वारा 1974 में प्रारंभ किया गया था, 1976 में आये बढ़ावा दिया था और 1980 में पुनः सता में आने के बाद जिसे और बल प्रदान किया गया था। मौजूदा कर ढांचे को एक ऐसे स्तर पर ले आया गया है जिसे मैं व्यार्थापूर्ण और पूर्णतः उचित मानता हूँ। मुझे आशा है कि उपयुक्त उपाय का हमारी कर संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा और उससे अधिक सही आय विधित करने की ब्रेणा मिलेगी।

69. इसके साथ-साथ, कर-प्रस्तावन को सख्त बनाने और उसे कर-वातावरों की अस्तुलतों के अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी होगा कि कर-विधारण के काम को जहाँ तक हो सके कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की जाए। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, संक्षिप्त कर-विधारण योजना की परिधि में 1 लाख रुपए तक की आय आ जाती है। इस सीमा के भीतर आने वाली आमदनियों के केवल कुछ प्रतिशत मामलों की ही जाति पड़ताल की जाती है, और ऐसे मामलों को यदृच्छिक नमूने के आधार पर चुना जाता है। 1983-84 में संक्षिप्त कर-विधारण के 85 प्रतिशत कार्य को पूरा करने का सदृश्य है। मैंने आय कर विभाग को कर निर्धारण के काम में और उसी लाने की हितापूर्ति दी है।

70. पिछले कुछ वर्षों से आय-कर अधिनियम में ऐसे उपबन्ध शामिल हैं जिनसे केवल उत्तरी सरकार को ऐसी अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है। इस शक्ति का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है, जहाँ सम्पत्ति के अन्तरण का बोयित प्रतिक्रिया (कन्सिडरेशन) उचित बाजार मूल्य से कम हो। अधिक संख्या में अपेक्षाकृत कम मूल्य वाले मामलों को निपटाने में जो अनुसूचक काम होता है, उससे बजार के उपबन्ध से और बाजार भावों में हुई दृष्टि को बेजोड़े हुए, मैंने उक्त उपबन्ध को इस प्रकार संशोधित किया है जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में ही किया जाएगा, जहाँ उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपए से अधिक होगा। इसे और सख्त बनाने के लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है कि पंजीकरण अधिकारी के समय विहित विवरण केवल उन मामलों में दाखिल किया जाएगा जहाँ अन्तरण के प्रतिक्रिया का मूल्य 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा के स्थान पर 25,000 रुपए से अधिक होगा।

71. मैं समझता हूँ कि दरों में कमी किए जाने से अब उन लोगों के प्रति वर्तमान दिवाने का कार्ड बहाना नहीं रहेगा जो हमारे कानूनों का अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों के बारे में अनिवार्यतः कड़ाई से कार्रवाई करनी होती है। कर अपर्चन और कर-व्यवर्तन को हतोत्साहित करने के लिए मैं कुन और उपाय भी लागू कर रहा हूँ। ऐसे सभी मामलों में, जहाँ कुछ कार्रवाई 20 लाख रुपए से अधिक की हो, अपना जहाँ किसी व्यवसाय से दूरी तक प्राप्ति 10 लाख रुपए से अधिक की हो, मैं लेखांशी की अनिवार्य लेखा-परीक्षा करने का उपबन्ध कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेखा पुस्तकों और अन्य अविदेश उचित रूप से रखे जाएं। और उससे करावान की व्यापक आमदनी सही रूप में प्रकट हो। मैं यह भी प्रस्ताव कर रहा हूँ कि 10,000 रुपए अथवा उससे अधिक की उड़ाव अथवा जमा राशियाँ केवल रेखित चेकों या बैंक शाफ्टों के

जरिए ही ली या स्वीकृत की जाएगी।

72. मैंने देखा है कि आय-कर अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि बेनामी रूप से धारित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विसी अधिकार के प्रतीक्षन के लिए वैध मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी स्थायान्वय में तब तक वाद दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने आय-कर की किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय अथवा निवेश घन की किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की घोषणा न कर रखी हो या इस सम्बन्ध में आय-कर अधिकारी को विहित फार्म में सूचना न दे रखी हो। इस समय ऐसी विवरणी या सूचना वाद दायर करने से पहले कभी भी वी जा सकती है। सम्पत्ति के बेनामी घारण की पद्धति पर नोक लगाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि अब से सभी मामलों में सम्पत्ति के अर्जन के एक वर्ष के अन्वर-अन्वर आय कर आयुक्त को विहित फार्म में सूचना देना अनिवार्य होगा। इस संशोधन से विभाग सम्पत्ति के ऐसे बेनामी अर्जन के सम्बन्ध में, अवधि के समाप्त होने से काफी पहले ही, उपमुक्त कार्रवाई शुरू कर सकेगा।

73. निगम-भिन्न खेत के बाद अब मैं अपना व्याप निगम खेत की ओर लाता हूँ। इस खेत के लिए कर की दरों में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं एक सुविधा दे रहा हूँ। पिछले वर्ष, कम्पनियों द्वारा देय अधिभार को 2.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत करने समय में कम्पनियों को अतिरिक्त अधिभार की राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा कराने का विकल्प दिया था। अब मैं यह उपबन्ध कर रहा हूँ कि कम्पनियों इस विकल्प का प्रयोग उनके द्वारा देय अधिभार की समूची राशि के सम्बन्ध में कर सकती है। यह साधन निगम खेत के पास बापस लौट आयेंगी और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध होंगी। अपने भाषण के पहले भाग में, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नरम शर्तों काने आर्णों की योजना के असर्गत विषय जा रहे 4 करोड़ रुपए तक के आर्णों के व्याज की दर को बढ़ाने के नियंत्रण का उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ।

74. विभिन्न खेतों से अध्यावेदन प्राप्त हुए थे कि प्रबन्धसिय पारिअधिक मी कटौतीयोग्य राशि की जो सीमा आय-कर अधिनियम में निर्धारित है। वह कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे सवन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रबन्धसिय पारिअधिकों में जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें देखने हुए, मैं भी प्रबन्धकों के बेतन की उच्चतम सीमाओं को 5,000 रुपए से बढ़ा कर 7,500 रुपए प्रति मास कर रहा हूँ लेकिन परिविधियों से स्वविधित उच्चतम सीमा अपरिवर्तित रहेगी।

75. चाय के उत्पादन और विनिर्माण का कारोबार करने वालों के लिए भी कुछ रियायतों की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा उपबन्धों में चाय की ज्ञानियों के पुनः रोपण अथवा प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त आधिक सहायता के सम्बन्ध में ही कर से छूट की व्यवस्था है। मैं कर की इस छूट को छूट खेतों के कायाकल्प और उपयन की अन्य अनुमोदित योजनाओं के लिए प्राप्त आधिक सहायता पर भी लागू कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस उपयोग से चाय के उत्पादन की बढ़ावे की बहारी योजना को मदद मिलेगी।

76. मुझे विश्वास है कि मेरे अगले प्रस्ताव का स्वागत बहुत अधिक सोगों द्वारा किया जाएगा। इस समय निवेशकर्ता आर्णपत्रों पर व्याज और लाभों, खोल पर कर की कटौती कराए बिना, प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे आय-कर अधिकारी से लिया गया छूट प्रमाण-पत्र भर कर दे या इस आय का एक घोषणा-पत्र दाखिला कर मैं कि उस वर्ष उनको आय छूट की सीमा से नीचे है। कागजी कार्याई को कम करते और छूट निवेशकर्ताओं की अमुविधा से बचाने के लिए मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ कि अब से बहुजनधारित कम्पनियों आर्णपत्रों के व्याज और लाभों आय की 1,000 रुपए तक की राशि की व्यायामी सीमा पर कर कर

की कटौती किए बिना कर सकती है, बासत कि व्यायामी शास्त्रीय (अकाउंट पेर्स) दैक अवया वैक इमप द्वारा भी जाए।

77. अध्ययन महोदय, मेरे वेष्टने में आया है कि करदाताओं का एक वर्ष कर कालूनों के कठिनय उपबन्धों का दुरुपयोग कर रहा है। पिछले वर्ष मैंने पूर्ण और धार्मिक न्यासों और संस्थाओं के कराधान के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की थी। मैंने देखा है कि वित अधिनियम, 1983 द्वारा न्यास निधियों के निवेश की जो पद्धति निर्धारित की गई थी, कुछ न्यास उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे सभी न्यास और संस्थाएं निर्धारित निवेश पद्धति का कार्रवाई से पालन करें और इस आय अथवा सम्पत्ति का इस्तेमाल व्यवस्थापकों और न्यासियों अविक को साथ पहुँचाने के लिए न किया जाए। इसलिए मैं दोषी न्यासों और संस्थाओं की आय पर आय कर की अधिकतम सीमान्तिक दर पर कराधान का उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. मैं इस विषय पर चर्चा करते समय यह उल्लेख करता चाहूँगा कि ऐसे न्यासों की स्थापना करवे की प्रवृत्ति देखने में आई है जो कारोबार करने हैं। इस प्रवृत्ति पर अचूक लागतों के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि जहाँ ऐसे न्यासों को कारोबार से मुकाफा और अभिनाश हो, वहाँ न्यास की समूची आय पर अधिकतम सीमान्तिक दर से कर लगाया जाएगा; लेकिन जिन मामलों में न्यास की स्थापना बसीयत के जरिए आधिक सम्बन्धियों के लिए की गई हो, केवल उनमें अपवादस्वरूप ऐसा नहीं किया जाएगा।

79. जो एक अन्य आवालीय बात द्यान में आई है, वह है निश्चित निकायों द्वारा तथाकायित कल्याण निधियों में भारी मात्रा में अंगदान करने की प्रवृत्ति मुझे यह भी पता चला है कि इन निधियों का उपयोग मनमर्ही से किया जाता है और इन पर कोई अनुशासन लागू नहीं होता। अतः मैं यह उपबन्ध कर रहा हूँ कि केवल कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई निधियों अथवा किसी अनुमोदित भविष्य निधि, अधिकार्यिकी की निधि अथवा उपदात निधि में किए जाने वाले अंगदानों के सम्बन्ध में ही कटौती उपलब्ध होगी। मैं यह परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से कर रहा हूँ ताकि अनाबश्यक मुकदमेवाली से बचा जा सके।

80. पिछले वर्ष मैंने निर्यात कारोबार से सम्बन्धित योजना को उदार बना दिया था। मेरा इसे जारी रखने और कुछ अधिक लंबी अवधि तक इसके कार्यवालत पर नजर रखने का विचार है।

81. पिछले वर्ष मैंने उन विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों का भी उल्लेख किया था, जो समय पाकर हमारी कर-प्रणाली का अंग बन गई है। यथापि यह हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का अपने आप में कोई लाभ हो, लेकिन कुल मिला कर इनका परिणाम यह हुआ है कि कर प्रणासन बड़ा बैचीदा हो गया है और कर-परिवर्जन अथवा कर-भवनवान तथा मुकदमेवाली के रास्ते खुल गए हैं। इसलिए मैंने इनकी समीक्षा करने और जहाँ अवश्यक हो वह ऐसी रियायतों की समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी, जिनकी अब कोई उपयोगिता न रही हो। मेरा इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ाने का इरादा है।

82. हमारा अनुभव यह है कि व्यय पर आधारित रियादत के परिणामस्वरूप व्यय को बड़ा बड़ा कर दियाने की प्रवृत्ति बन जाती है और इसलिए हमारी कर-प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध सारी भागित कटौतियों को बापस ले लिया जाए। कास्तविक रूप में किए गए व्यय को कटौती के नियंत्रण विस्तरित अंतर्गत आद्यता प्राप्त होती रहेगी। केवल भारतीय (वेटेज) का लाभ अब प्राप्त नहीं होगा।

83. मैं आय-कर अधिनियम की धारा 33व, 35व, 80व और 80ड में अन्तर्गत उपलब्ध छूटों की भी बापस ले रहा हूँ। इस बात के बावजूद कि इन कटौतियों के उद्देश्य उपरी लौट प्रशस्तीय हैं, इनका दुरुपयोग किया जाता रहा है अथवा इनसे केवल कुछ ही लोगों

को लाभ पहुँचा है। इनमें संबंधित राजस्व की राणि बड़ी मामूली है। मैं धारा ४०८, ४०९, और ४०१, के अन्वर्यां उपलब्ध छुट की मात्रा में भी कर्मा कर रहा हूँ।

8.1. अब मैं भ्रन-कर अपेंटिनेट के मध्यवन्ध में कुछ रियायतों की पोषणा करना चाहता हूँ। मुझे यहीन है कि सम्मानित मदरस्य यह मुन कर प्रसन्न होंगे कि किसी एक करदाना के स्वामित्व वाले एक मकान के मध्यवन्ध में छूट की भौतिक सीमा को 1 लाख रुपए के भोजूदा भर दें बड़ा कर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। बाजार मूल्यों में हुई वृद्धि देखने हुए ऐसा किया जा रहा है। मैं विशिष्ट विनीय परिस्थितियों के संबंध में छूट की सीमा को भी 1,65,000 रुपए के अंतर्मान स्तर से बड़ा कर 2,65,000 रुपए करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। भारतीय युनिट ट्रस्ट के यूनिटों के संबंध में उपलब्ध 35,000 रुपए की पृथक छूट के माध्यमिका विनाश राष्ट्रीय जगत योजना के अन्तर्गत जमा-राशियों पर किए जाने का प्रस्ताव है, विशिष्ट विनीय परिस्थितियों के मध्य के संबंध में समय छूट की भोजूदा 2 लाख रुपए की अविकलन सीमा बढ़ा कर 3 लाख रुपए हो आएगा। सम्मानित मदरसों को याद होगा कि वैत अपने भावण के पहले भाग में वित्तीय परिस्थितियों के हृष्ट में अन्तर्मान जूलाते में हुई सकपता का जिक्र किया था; मुझे आणा है कि इस परिवर्तन में उधरे और विद्य होगी।

४३. प्रत्यक्ष करों के माध्यम में मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन अपेक्षाकृत मामूली किस्म के हैं और मैं उनके विनाश में जा कर इस सद्वन का अहमत्य अभ्युत्त्व नहीं लेना आहेत।

४६. कनिपय ग्रियान्तों को बापस लेने अवधार उनमें फेर-बदल करते के फलस्वरूप राज्यवंश में भी बुद्धि होगी उन्हें त्रिमात्र में लेने के बाद, धायकर से सम्बन्धित मेरे प्रमाणों से 75 करोड़ रुपए की निवाप हानि होगी, जिसमें केवल की 36, 32 करोड़ रुपए और राज्यों को 38, 68 करोड़ रुपए की हानि होगी।

87. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करने से संबंधित अपने प्रस्तावों की सचाई करना। यह मैंग मुख्य उद्देश्य कुछ सोच विचार कर बुने हुए क्षेत्रों में उनाव-शुल्कों में थेटेप्र गहर और टेक्निक व्यवयोजनों के जरिए भारतीय उद्योगों के विकास को और बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मैंने उपभोक्ताओं के लिए कुछ मद्दों की कीमियों को घटाने और अप्रत्यक्षस्था में मुश्किलियों की दर को नियंत्रित रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है। मैंने विश्वास है कि नमस्तिति नवस्थों को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा करने का मैंने थोड़ा भरकारी राजस्वों का भी ध्यान रखा है।

88. सीमा शुल्कों में मर्वित मेंदा प्रमुख प्रस्ताव महायक सीमा-शुल्कों के बारे में है। 1973 के बजट से आधिक आवार पर लगाया गया शुल्क को 31 मार्च, 1983 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। मैं कहु अपवादों के माथ, वर्षमान प्रभावी वरों में 5 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं उर्वरकों जैसी आवश्यक भद्रों, केरोसीन तथा हाई स्पीड डीजल लेन जैसे खुले पेट्रोलियम उत्पादों और अध्यात्मिक कागज को भी इस प्रस्तावित वृद्धि से अत्यध रखना चाहता हूँ। इन प्रस्तावों का विभूत अधिक बजट वर्षों में उपलब्ध है। इस प्रस्ताव में एक पूरे वर्ष में 241 73 करोड़ रुपए का अनिवार्य राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

89. कूड़ पेट्रोलियम पर 9.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हितावध से इस समय जो सीमांशुल्क लग रहा है (जो सहायक शुल्क के रूप में लिया जा रहा है) उसकी यह दर 1973 में सिध्धार्थित की गई थी। पेट्रोलियम उत्पादों की आनंदरिक कीमतों पर कोई प्रभाव ढाले बिना, मैं कूड़ पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उत्तर से राजस्व में 132.76 करोड़ रुपए का आयदा होगा। शुल्क की इस दृष्टि को कम्पनियों स्वयं सह लेती नीर 1513 GJ/83-2

उन्हें इसकी वजह से उपभोक्ता की सत्ता में कोई विद्युत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

90. लोहे और इस्पात की मर्दों पर आयात-शुल्क की वृद्धिमात्र वरे कुछ सात गहरे तरफ की गई थी और इस मध्य वे स्वदेशी उत्तोंग की आवश्यकताओं के अनुच्छेद नहीं रही हैं। मैं लोहे और इस्पात (स्टेनेम स्टील में भिन्न) की भिन्न-भिन्न मर्दों पर बृतियादी सीमा शुल्क में, शुल्क की सौज़दा वरों को दृष्टिगत रखते हुए, 5 प्रतिशतांशों अवधा 10 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि स्टेनेम स्टील की मैट्रिंग स्टैम पर, जो इस नमय भीयाशुल्क से भूल्क है, कुल मिलाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुमार की दर से सीमाशुल्क लगा दिया जाए इन उपायों से 84.20 करोड़ रुपए का अनियिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

91. मैं जिप कामरां तथा उनक हिस्सों, मेनेटिक ट्रोंसों और पेट्रोलियम की विधिएं वस्तुओं, अर्थात् पेट्रोलियम जैवी, सोडियम पेट्रोलियम अन्कोनेट और लिकिड पेरफीन पर आयाम-शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों का ब्योरा बजट पतों में उपलब्ध है। इन प्रस्तावों में कोई 5.32 करोड़ रुपया के राजस्व की प्राप्ति होनी।

92. रत्नों और आभूषणों के महत्वपूर्ण लेव में नियतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रत्नों और आभूषणों का प्रसेस्करण और विनिर्माण करने वाली कई-एक मशीनों पर लाने वाले सीमान्तरिक को मीजूड़ा दरों की घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। रत्न प्रसेस्करण मशीनों से प्रसेस्करण की प्रक्रिया में होने वाली हानि बहुत कम घट जाएगी और उनमें कुप्रसिलाकर उनकी गुणवत्ता (कानिंहटी) और उत्पादकता बढ़ जाएगी। इन प्रकार, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि आद्य वस्तुओं के पैकेज बनाने में इस्तेमाल में आने वाली और मात्र तथा आद्य प्रसेस्करण उद्योगों द्वारा काम में ली जाने वाली विनिर्मिट मशीनों पर लगने वाले सीमान्तरिकों की मीजूड़ा दरों को घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। आणा की आनी है कि इससे मूल्य योगिन रूप में और खुले रूप की जाएँ उत्पोदकों पैकों में आद्य वस्तुओं के नियति को प्रोत्साहन मिलेगा उपर्युक्त प्रस्तावों से कोई 5-25 करोड़ रुपा के राजमूद्रा की हानि होती।

93. मरीनी औजार प्रीशोधिनी में उननि ही जाने के कारण, परंपरागत मरीनी औजारों के स्थान पर सी०ए०न०सी० मरीनों का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ना जा रहा है क्योंकि उनकी उत्पादकता अधिक होती है और वे अधिक मरी होती है। में सी०ए०न०सी० प्रणालियों पर लगने वाले सीमा-मुक्त को बटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि खट्टेशी मरीनों विनियमिता सी०ए०न०सी० मरीनी औजारों को प्रतियोगितात्मक दरों पर दे सके। इसमें 0.82 करोड़ रुपये के राजस्व का व्याप करना होगा।

94. कागज उद्योग को उसकी कच्ची सामग्री उचित कीमतों पर सुलभ कराने के लिए और प्रगत बन्य भारतीयों पर दबाव को कम करने के लिए, मैं कागज या गना बनाने के काम आने वाली लुगदी बनाने के लिए लकड़ी की खरिदियों को सीमावरुद्धों से पूरी तरह भूक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कागज बनाने के लिए आयान की गई लकड़ी की लुगदी पर एक को मीजूदा स्तर से छटा कर 30 प्रतिशत कर दिया जाए। ऐसा करने में 1.10 करोड़ साल के जटिल की हानि होगी।

१५. मीमांसुक अधिनियम, 1962 के अनुचारण प्राप्ति विवरों से गवाई उपसंघों में और मीमांसुक टेरिक अधिनियम, 1975 के उपसंघों में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का व्यापक विवरण में लिया गया है।

५६. महोदय, प्रब मैं उगादणुकों संबंधी अपने प्रस्तावों की ओर अनिय हू। मेरे इन प्रस्तावों के मुख्य उद्देश्य हैं: भुवास्त्रीनि के प्रभावों को खत्तम कराना, कर परिवर्तन और अपवर्णन की गणांश को 'कर

करता, मांग की मंत्री से प्रभावित जुने हुए उद्योगों को सहारा देना और पहले से निमित अमता तथा तिवेश का बैंकर उद्योग सुनिश्चित करता।

97. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष उत्पाद-शुल्क मीमूला दरों पर और वर्तमान छूटों के साथ 31 भार्द, 1985 तक लाग रहे।

98. राहत से संबंधित भेना पहला प्रस्ताव खांडमारी जीती के बारे में है। मैं खांडमारी को जीती को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त करना चाहता हूँ। इस उद्योग के अम-प्रधान स्वरूप को देखते हुए और इस उद्योग में रोजगार की वृद्धि के और अवगम सुधार करने के लिए मैं यह छूट दे रहा हूँ। उत्पाद-शुल्क हटा दिया जाने से, यह उद्योग गल्ला उत्पादकों को उनके गन्ने की अच्छी कीमत दे सकेगा, और इसमें दूर्घटना के देहाती इलाकों में स्थित अनेकों खांडमारी के एककों को राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव के कारण 16.42 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा। भुमि यह भत्ताया गया है कि खांडमारी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यदि इस उपाय के फलस्वरूप, देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो मैं आप्ता करता हूँ कि इमका शेष, मेरे प्रतिष्ठित 'सहयोगी स्वास्थ्य' मंत्री मंत्रीशय को तहीं बनिक मुझे मिलेगा।

99. सम्मानित सदस्यों द्वारा याद होगा कि 1978 के बजट में जितना पर उत्पाद-शुल्क, राजस्व के उपाय के रूप में, लगाया गया था। जितनी पर प्राप्त होने वाले शुल्क की सारी निवल राशि राज्यों में वितरित कर दी जाती है। जितनी पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और यह राज्य सरकारों पर छाड़ा जा रहा है कि वे जहाँ तक चाहे और जिस तरीके से चाहे, इस खोन का उपयोग कर लें। इससे राज्यों का साधान जुटाने का एक और लेन मिल जाएगा। मैं राज्यों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कुछ समय दे रहा हूँ। उत्पाद-शुल्क हटाने का यह प्रस्ताव 1 अक्टूबर, 1984 से प्रभावी होगा।

100. कपड़े को सस्ता करने के उद्देश्य से मैं कपड़ा उद्योग को भी काफी राहत देना चाहता हूँ। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 और 1983 के बजटों में पालिएस्टर के बांधनीय अनुमतियों के साथ मिश्रित किस्मों के कपड़े के उत्पादन को प्रीत्साहन दिया गया था। ऐसे कपड़े अधिकारिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन उद्योग को और राहत देने के लिए और ऐसे कपड़ों को मल्टी कीमतों पर मुलाक करने के सर्वोपरि उद्देश्य है, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि 40 प्रतिशत में अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर वाले पालिएस्टर-काटन बैंडेड याने पर लगने वाले कुल उत्पाद-शुल्क को बटायार 5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए। ऐसे दार्ता पर लगने वाले शुल्क की भौजूदा दरें, आमतौर पर, पालिएस्टर-काटन मिश्रण के अनुपात के आधार पर, 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.5 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं। मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर के भौजी मिश्रणों पर उमी शटी कुछ दर में शुल्क लगेगा। पालिएस्टर और विस्केप के इनी प्रकार के मिश्रणों पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा। जबकि शुल्क की वर्तमान दरें आमतौर पर 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं। इन परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में अनुमानतः 33.25 करोड़ रुपए के गजस्व की ज्ञान होगी।

101. मेरा ध्यान मिश्रित कपड़ों (डीईड फेनिक्स) की ओर भी गया है। पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिनमें पालिएस्टर की मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम हो, उत्पाद-शुल्क को बटा कर 2 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाएगा। ऐसे कपड़ों पर इस मध्य 7.5 प्रतिशत से 17.8 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न वर्षों पर मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क लगता है। इस रियायत से एक पूरे वर्ष में राजकीय फों 26.50 करोड़ रुपये कम प्राप्त होंगे। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि यह 2 प्रतिशत मूल्यानुसार का शुल्क बिक्री-कर के एकजू में अनिश्चित

उत्पाद-शुल्क के रूप में बगूल किया जाए। ऐसा कि सम्मानित मदम्पो को मालूम ही है, वस्तों पर लगने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क की प्राप्तियां गर्भों को मिलती हैं।

102. पालिएस्टर मिश्रित सूती याने भी पालिएस्टर मिश्रित गूती कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के बांचे में किए जाने वाले इन पर्वतनों से, 67:33 के अनुपात वाले मिश्रित के मामता में संगमग 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की योक कीमत वाले और 35 रुपए से 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की शुद्ध भीमित वाले कपड़े पर शुल्क में संगमग 3.30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कमी होती है। इस प्रकार शुल्क कम किए जाने में कपड़ा उद्योग ऐसे कपड़ों को कम कीमतों पर बेच सकेगा।

103. मैं युनी कपड़ों पर भी राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ जिनका देण में कपड़े के कुल उपयोग में अब भी काफी बढ़ा रहा है। मैं 51 से कम कारंट वाले और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक के निर्धारणीय मूल्य के सूती कपड़ों पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्मिश्रित (कंपोजिट) मिलों के प्राप्तने में, ऐसे कपड़ों पर इस मध्य 2.38 प्रतिशत से 3.56 प्रतिशत तक की मिश्न-भिन्न मूल्यानुसार दरों पर उत्पाद-शुल्क लगता है। पावरलूम और हैडलूम के कपड़ों का संसाधन करने वाले स्वाधीन संसाधकों के मामले में शुल्क की रियायती दर खाने होती है। में स्वाधीन संसाधकों द्वारा संसाधित उपयुक्त किस्मों के हैडलूम और पावरलूम के कपड़ों को पूरी तरह शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्मिश्रित मिलों के कपड़ों के लिए शुल्क की दर को भी घटाकर 1 प्रतिशत मूल्यानुसार निया जा रहा है और इस प्रकार स्वाधीन संसाधकों और सम्मिश्रित मिलों के बीच के भौजूद अनुर को संगमग कायम रखा जा रहा है। यह शुल्क बिक्री-कर के प्रश्न में लगने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क के रूप में होगा और यह पूरा का पूरा राज्यों को मिलेगा। ऐसे कपड़े अधिकतर समाज के कमजोर बांगे ने लोगों द्वारा हस्तानाम किए जाते हैं। शुल्कों में की जाने वाली इस कमी का फायदा यह होगा कि इन बांगों के लोगों को यह कपड़ा सस्ती कीमतों पर मिलेगा। सूती कपड़ों से संबंधित इस प्रस्ताव से 28.40 करोड़ रुपए के गजस्व की जानि होगी।

104. मैं प्राप्ता करता हूँ कि मेरे प्रस्तावों से कपड़ा उद्योग को भी मदद मिलेगी। कपड़ों की कीमत कम हो जाने की वजह से उनकी मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग को कायदा पहुँचेगा।

105. आप रील हैंडों के लप में सूती याने और सेल्यूसिक्स स्पन याने का इस्तेमाल हाथकरथा थेल में बगाबर बढ़ता जा रहा है। 'हाथ-करथा वर्ग' में, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजीकृत हाथकरथा महफारी मिश्रितों अथवा हाथकरथों के विकास के लिए स्थापित या अनुमोदित गंगड़ों को सम्माइ जिए जाने वाले ऐसे याने पर शुल्क-भार में संगमग 50 प्रतिशत की कमी कर दी जाए। इसमें एक पूरे वर्ष में गजकोष को 3 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावों से जो राजस्व की हानि होगी उसको कुछ हव तक पूरा करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक के निर्धारणीय मूल्य के मानव-निर्मित कपड़ों पर बिक्री-कर के बाले में लगाने वाले प्रतिरक्षित उत्पाद-शुल्क की दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। यह वृद्धि उन मिश्रित कपड़ों के मामले में साधा नहीं होगी जिनके बारे में शुल्क कम किया जा रहा है। इसका असर उन अधिक कीमती कपड़ों पर पड़ेगा जिनका इस्तेमाल मूल्यानुसार समाज के अधेश्वर अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। उन्हें इसका बुरा नहीं मानता चाहिए। हां उपाय में, गजकोष को एक पूरे वर्ष में 27 करोड़ रुपए मिलेगे और यह गति भी गर्भों के हिस्से में आएगी।

107. मैं शोटी कम्बलों और सम्मिश्रित मिलों द्वारा संसाधित शोटी याने से ब्रैंडे ही अन्य कम्बलों पर लगने वाले शुल्क में संगमग 7 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि ऐसे शोटी कम्बल स्वाधीन मंसाधकों द्वारा संसाधित किए जाएंगे तो उन पर शुल्क में पूरी कुछ दी

जाएगी। इस प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

108. एक अन्य उद्योग जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वह कागज उद्योग है। यह उद्योग कच्ची सामग्री और अन्य निकिटियों की ग्रहणी हुई लागत के कारण एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य कागज और गते (पेपर बोर्ड) के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और दुर्भागी प्राकृतिक वन्य साधनों की रक्षा करना है। मैं कागज बनाने के लिए लकड़ी की अचिन्तियों और लकड़ी की लुगदी के आवाय पर मीमा-शुल्क से प्रस्तावित छूट का पहुंच ही उन्नेख कर चुका हूँ। गहन देने के एक और उपाय के रूप में, मैं छाई तथा लियाई के बागज और कागज की बड़ी मिलों द्वारा उत्पादित क्राफ्ट पेपर पर भी बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 425 रुपए प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ; और ऐसे कागज पर लगने वाले शुल्क में तबनुस्पति रियायत दी जाएगी यदि उपकों बानने में अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ ही अनुलेप्य अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों की श्रेणी का भी विस्तार किया जा रहा है।

109. इस समय गते के मामले में अपरंपरागत कच्ची सामग्री के इस्तेमाल के लिए कोई रियायत उपलब्ध नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम से कम 50 प्रतिशत अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों से वो गतों पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क को, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार + 1430 रुपए प्रति मेट्रिक टन के बत्तमान सामान्य स्तर से घटाकर 560 रुपए, 900 रुपए अथवा 1120 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाए जो इस बात पर निर्भर करे कि ऐसी कागज की मिलों से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कागज और गते की निकासी क्रमशः 3,000 मेट्रिक टन, 7,500 मेट्रिक टन अथवा 16,500 मेट्रिक टन से अधिक नहीं हुई थी। अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल करने वाले बड़ी कागज मिलों के लिए गते पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को घटाकर 7 प्रतिशत मूल्यानुसार + 825 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है।

110. कागज उद्योग से संबंधित मेरे प्रस्तावों से उत्पाद-शुल्कों में एक पूरे वर्ष में 33 करोड़ रुपए की हानि होगी। लकड़ी की अचिन्तियों और लकड़ी की लुगदी के आवाय पर प्रस्तावित मीमा-शुल्क संबंधी हूँटों के साथ मिलकर इन प्रस्तावों से, आशा है, स्वतंत्रे कागज उद्योग के विकास का यथेष्ट राजकीय समर्थन मिलेगा और उचित शोधतां पर कागज की उपलब्धता बढ़ेगी।

111. सम्मानित मदस्यों को माद होगा कि कानिपय विनिदिष्ट वस्तुओं के मामले में, अक्टूबर, 1983 में कुछ समय-बहुत रियायतें दी गई थीं। उस उपाय के प्रति, जो बुद्धिमाली मानों को पैदा करके उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य में किया गया था, उद्योग को प्रतिक्रिया को देखते हुए, मैं इस रियायत को, कुछ परिवर्तनों के साथ, एक वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. वाणिज्यिक बाहनों और तीन-नक्षल बाल बाहनों के मामलों में, रियायत को जारी तो रखा जाएगा, लेकिन अक्टूबर, 1983 में शुल्क में दी गई रियायत को मात्रा में 2-1/2 प्रतिशतांशों को कमी की जा रही है। मैं कुछ हाल काण्डे वाणिज्यिक बाहनों के माइंडों को छूट के व्यापारिक स्तरों का लाभना करना हूँ ताकि उत्पाद-शुल्क की वर के मामले में ऐसे बाहनों के सभी माइंडों में समानता आ जाए। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 45 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

113. भूरक्षिकरणों, डीप फ्रीजरों और प्रणीतक उपसाधनों के हिस्सों आदि, स्टार्ज बेटरियां और धरने वाली बिजली के उपसाधनों के मामले में दी गई रियायतों को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इन मदर मदरों के कारण राजस्व में कुल मिलाकर कोई 19 करोड़ रुपए की हानि होगी।

114. वर्षों तथा दूरों के द्वायरों और सहक-भिन्न प्रयोजनों के लिए नाम में आगे बाले द्वायरों के मामले में, अक्टूबर, 1983 में दी गई

रियायत को जारी रखने का मेंग विवार नहीं है क्योंकि इस उद्योग द्वारा धोगिन मूल्य-बुद्धियों का ध्यान में रखने हुए हम रियायत को आगे जारी रखने का कोई आचित नहीं है। फिर भी, शुल्क पद्धति को मुक्ति-मापन बनाने के एह उपाय के रूप में और करन्प्रबंधन की गंजाई को नाम करने के विचार से मेंग मूल्यानुसार शुल्क दरों के स्थान पर अधिकांशतः मात्रानुसार शुल्क दरें अपनाने का प्रस्ताव है।

115. चीनी मिट्टी और पोर्पिलेन के बने आनेवाले के बर्तनों (टेब्लवेर्प) के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में गतिरोध के प्रासार दिखाई दे रहे हैं और उद्योग की क्षमता के उपर्योग में कमी हो रही है। इस उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं इन मदरों पर लगने वाली बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राजस्व में 1.5 करोड़ रुपए की हानि होगी।

116. गर्मी का मोसम ज्यादा दूर नहीं है, इसकिए मैं माननार्थ सदस्यों के भिजाज को ठड़ा रखने में उनकी सहायता करता चाहूँगा। मैं टेब्ल फैनों के मामले में बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने और उन भीलिंग फैनों के मामले में, जिनका व्याप 107 में० मी० से ज्यादा न हो, 15 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं डेजर्ट कूलरों सहित वाष्पिक कूलरों पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की 40 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर को 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से राजस्व में 5,10 करोड़ रुपए की हानि होगी।

117. शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में, मैं आवेदन तारों के बुनियादी शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत और ताम्बे की तारों के छड़ों के बुनियादी शुल्क में 1300 स्पैष्ट प्रति मेट्रिक टन की बुद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुल मिला कर, इन परिवर्तनों से राजस्व में न तो हानि होगी और न ही लाभ।

118. ऐसा कि गम्भीरता सदस्यों का याव होगा, बहुत से विषयात कलाकारों ने एक अपील प्रकाशित की थी जिसमें कला की चोरी (पाइरेसी) को और हृपारा ध्यान आकर्षित किया गया था। चूंकि मैं इन प्रतिनिधित्व कलाकारों की उमेशी नहीं कर सकता, अन्विष्ट में आवाज मेरे केंद्रों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस मदर पर दुर्दि राजस्व हानि मेंटेनिंग टैक्सों पर सीमा शुल्क में की गई बुद्धि में लगभग पूरी हो जाने की आशा है।

119. राहत के एक सामान्य उपाय के रूप में मैं खादी और प्रापोड्योग आयोग के एकों छारा निमित्त लांडरी साबुन को पूर्ण रूप से उत्पाद-शुल्क से सुकृत करने का प्रस्ताव करता हूँ और नकली आमूल्यों, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों, लासटेनों की कांच की चिमियों, उच्च दुश्लता वाले लकड़ी के स्टोरों, छतरियों और सेवीन औरी आम उपसाग की कतिपय मदरों पर उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत में घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन रियायतों से 1,13 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

120. गम्भीरता सदस्यों का याव होगा कि उत्पादन-बृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए गत दो वर्षों से एक उत्पाद-शुल्क राहत योजना लागू है। मैं इस योजना को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

121. गम्भीरता सदस्यों को यह भी याव होगा कि पिछले बजट में, मैं भारे और इसाम की मदरों से संबंधित टैरिक को युक्तिसंगत बनाया था। इस वर्ष मैं अलगी धारुओं के मामले में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया हूँ। टैरिक की प्रविष्टियों को अधिक ऐक्सानिक आवार पर संरक्षित किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भारती इन परिवर्तनों को भी किसी बाव द्वारा तारीख में लागू किया जाएगा। लब तक शुल्क जी लौजारा प्रभावी दरें आगू रहेंगी।

122. मैं मिगरेंटों पर अनियादि उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इनियादि उत्पाद-शुल्क और अनियिक उत्पाद-शुल्क के भीच के भीजूदा अनुपात को संशोधित करने उसे 1.75 : 1 बनाया जा रहा है। इस उत्पाद के परिणामस्वरूप ग्रामीणी वित वर्ष में भुनियादी उत्पाद-शुल्क खाते में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क खाते में 42.89 करोड़ रुपये अन्तरित हो जाएंगे और इस प्रकार राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी। भुनियादी उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित राशि में उतनी ही कमी हो जाएगी। मिगरेंटों पर उत्पाद-शुल्कों के कुल भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

123. कुछ अन्य छाट-साटे प्रस्ताव भी हैं जिनका राजस्व की वृद्धि से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इनमें, कुछ सामलों में उत्पाद-शुल्कों में पुनः समायोजन करना और कुछ उत्तरी रेलिंग वर्डों को सूची से हटाना शामिल है जिन्हें काफी समय से पूर्णतः छूट प्राप्त है।

124. आयकर अधील अधिकरण तथा सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के कार्यालय में प्राप्त हुए अनुभव को वृद्धि गत रखते हुए, इनसे संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये संशोधन मुख्यतः प्रशासनिक स्वरूप के हैं। मैं इन प्रस्तावों का वर्णन करके सबन का समय नहीं लेना चाहता।

125. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त राजस्व में, जो 1953-54 में लगभग 100 करोड़ रुपए था, प्रसाधारण वृद्धि हुई है और यह बहु कर 1983-84 में 10,100 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, और इसके साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ़ में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, जब टैरिफ़ को युक्ति-संगत बनाने के लिए, जिसमें पिछले तीन वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है, इसकी व्यापक रूप से समीक्षा की जाए। इसके लिए व्यापक प्रध्ययन की आवश्यकता होती है। जिसे केवल कोई तकनीकी अध्ययन वल ही अच्छी तरह से कर सकता है। अतः मैं एक ऐसे बल से गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

126. मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनसे सीमा-शुल्कों के रूप में 465.41 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के रूप में 33.10 करोड़ रुपए के अनियिक राजस्व की प्राप्ति होती है। भुनियादी शुल्क खाते से अतिरिक्त शुल्क (बिक्री कर के बदले) खाते में 43.64 करोड़ रुपए का अत्यरण होगा। सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 7.26 करोड़ रुपए की रियायत और राज्यों दी गई है। सीमा-शुल्कों से 458.15 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होती है। उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 189.33 करोड़ रुपए की निवल हाती होती है, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 148.95 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 40.38 करोड़ रुपए होगा। इसमें बिक्रीकर के एकज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के 52.31 करोड़ रुपए के हिस्से को भी हिस्साव में ले लिया गया है। इन अतिरिक्त कर प्रयत्नों से केन्द्रीय सरकार को पूरे वर्ष में 309.20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है।

127. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में किए गए परिवर्तनों को पहली मार्च, 1984 से प्रभावी बनाने वाली अधिकृतनामों की प्रतियां सभा-पट्टल पर पर्याप्तमय रूप दी जाएंगी।

128. मैं पहले बता चुका हूँ कि कराक्षान की मौजूदा दरों पर बजट में 2,035 करोड़ रुपए का धाटा होगा। अब प्रस्तावित कर उपायों और राहतों तथा रियायतों के कलास्वरूप केन्द्र को 272.88 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे 1,762 करोड़ रुपए का धाटा रहेगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि बजटीय बाटे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए। और मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इत्तमा धाटा हमारी परिस्थितियों के घनुमार उचित ही है। मुझे भाशा है कि हम यह बाटे कम उत्पाद को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के भेरे प्रस्तावों का प्रधान्यवस्था में मुद्रास्फीति भी प्रवृत्ति पर अनुकूल प्रभाव

पड़ेगा। इस अवसर पर मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह श्लोक उद्धृत करता चाहूँगा :—

एष कुर्यात्समुदयं वृधिं चायस्य दर्शयेत।

होम अवस्था च प्राजः साधयेन्व चिपर्यमम् ॥

129. चार बर्वे पूर्वे, मुझमें पिछों मुप्रतिष्ठित वित महीं महोदय ने इस गरकार का पहला बजट पेश करने समय देश की प्रवृद्ध्यवस्था को पहुँची तात्त्विकी को बूर करने और उसे स्थिरणा, निकाम और मामाजिक व्याप के मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के हमारे वृद्धि निश्चय का उल्लेख किया था। प्रध्ययन महोदय, हमने उम चतुर का पालन किया है।

130. महोदय, मैं यह बजट भवन का प्रस्तुत करता हूँ।

ए० रमाचार्ण, नंदुक भवन।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

Budget 1984-85 Speech of Minister of Finance

On 29th February, 1984

New Delhi, the 1st March, 1984

(PART A)

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1984-85.

2. The Budget has been formulated against the background of strong recovery in national income and agriculture, and an equally impressive improvement in our balance of payments. These and other developments in the economy have been covered in detail in the Economic Survey, presented to the House a couple of days ago. I shall, therefore, be brief in reviewing the current economic situation.

3. As the House is aware, the country had to go through two years of severe drought and one year of indifferent monsoon during the period 1979-80 to 1982-83. Foodgrains production, which had reached 132 million tonnes in 1978-79, declined to 110 million tonnes in the following year. It recovered to 133 million tonnes in 1981-82 but then declined again to 128 million tonnes in 1982-83 because of another severe drought. The current year has seen a major breakthrough in foodgrains production, and we are not only likely to recover lost ground, but, also improve substantially on the previous peak. Foodgrains production in 1983-84 is expected to exceed the target of 142 million tonnes. Agricultural production as a whole is likely to increase by 9 per cent over the previous year. Hon'ble Members will agree that this is convincing testimony to the soundness of our agricultural strategy and to the hard work of our farmers.

4. Industrial performance shows an improvement over the previous year, but the recovery in industrial production still seems weak. Industrial growth in the current year is likely to be about 4.5 per cent, compared with 3.9 per cent in 1982-83. For the four year period after 1979-80, industrial growth will average slightly more than 5 per cent. This is well below the potential of the industrial sector. We must aim at a growth rate of 7 to 8 per cent in industry if we are to maintain high rate of growth of GDP and provide employment for our growing labour force in the years ahead.

5. The national income growth in 1983-84 is likely to be in the range of 6 to 7 per cent. In the four years since the present Government took over, the average growth rate in national income has been about 5.4 per cent which is higher than the rate of growth in the first four years of any previous Plan. Per capita income in this period will have risen at an average rate exceeding 3 per cent per year.

This achievement is all the more noteworthy when viewed against the background of a highly adverse international economic environment, and a severe drought.

6. The years 1981-82 and 1982-83 were characterised by exceptionally low rates of inflation. The annual rate of inflation which had reached a high of 21.4 per cent in 1979-80 was brought down to 16.7 per cent in 1980-81 and further to only 2.4 per cent at the end of 1981-82. The annual rate of inflation at the end of 1982-83 was 6.2 per cent, which is unusually low for a drought year. But, there has been an acceleration in the annual rate of inflation in the current year despite an excellent crop. The initial delay in the arrival of the monsoon and the high liquidity in the economy exerted pressure on prices, in the early part of the year. The favourable effects of a good crop led to a decline in cereal prices after harvesting. However, this was largely offset by sharp increases in prices of a few commodities such as pulses, certain edible oils, rubber, tea and cotton because of both domestic and international factors. As a result, the seasonal dip in prices, which normally occurs towards the end of September has been weak.

7. As the House is aware, the Government has taken several measures to minimise the impact of the drought and to contain the price rise. Action was taken to increase procurement, availability, and releases of sensitive commodities such as wheat, sugar, and edible oils through the public distribution system. Steps were also taken to mop up excess liquidity with the banking system and to curtail Government expenditure. Exports of cotton and CTC teas were restrained in order to increase domestic availability. Further measures will be taken as required to ensure that there is no repetition of the experience of 1979-80, when prices were allowed to increase by over 21 per cent.

8. Let me now turn to the external payments situation facing the economy. In my budget speech last year, I had informed the House of the improvement that had taken place in our balance of payment in 1982-83. I am happy to say that this improvement has gained strength in 1983-94. The trade gap, which declined from Rs. 5800 crores in 1981-82 to about Rs. 5500 crores in 1982-83, is expected to decline further in the current year. Receipts on invisibles account have remained buoyant and the incentives for non-resident deposits have been highly successful. Our foreign exchange reserves, inclusive of IMF drawings, have increased by Rs. 662 crores in the current financial year upto 10th February.

9. Our strategy for bringing the balance of payments under control, after the sharp deterioration that occurred in 1979-80, has paid rich dividends. In view of the improvement in our payments position, the Government has voluntarily decided not to avail of the balance of 1.1 billion SDR under the Extended Fund Facility of the IMF. While intervening in the debate on the IMF loan in this House in December, 1981, the Prime Minister had this to say, and I quote :

"It does not force us to borrow, nor shall we borrow unless it is in the national interest. There is absolutely no question of our accepting any programme which is incompatible with our policy, declared and accepted by Parliament. It is inconceivable that anybody should think that we would accept assistance from any external agency which dictates terms which are not in consonance with such policies."

This was true then, and it is true now.

10. Belying the prophecies of doom by many a selfstyled Cassandra, the economy has emerged stronger as a result of the adjustment effort mounted by us. None of the dire consequences that we being warned about has occurred. We have not cut subsidies. We have not cut wages. We have not compromised on planning. We have not been trapped in a debt crisis. We have not faltered in our commitment to anti-poverty programmes or the welfare of our people. We entered into this loan arrangement with our eyes open. We have come out of it with our heads high.

11. We hope that our decision to forgo the balance of the amount available to us under the IMF loan would, in a small way, help the IMF to provide greater assistance to other developing countries. I must ask take this opportunity to express our appreciation for the goodwill and mutual understanding that has marked our relationship with the IMF during the entire period of the EFF arrangement.

12. However, there can be no room for complacency. We must persist with the policies that have brought about this favourable outcome. It is necessary to work even harder to save imports in critical areas and to increase exports. Our exports, net of oil, in the first seven months of 1983-84 increased by 9.9 per cent. This is a reasonable performance considering that world trade has been stagnant for quite some time. We would need to do even better in the future in order to meet the essential import requirements of a growing economy, and to keep the debt service ratio at a manageable level.

13. The Government has taken several steps in the last four years to mobilise resources for public sector investment and to increase the rate of public savings for financing the Plan. Apart from adjustment of the tax rates, the fiscal instrument has been used to provide stronger incentives for savings in the form of financial assets. Interest rates on deposits were also revised upwards with the same objective in view. These policies have been highly successful and the inflow of funds in small savings as well as time deposits has exceeded expectations. An important task of fiscal policy in the years ahead is to strengthen this trend.

14. In considering the strategy for resource mobilisation we have to recognise that while our tax rates are relatively high, the tax base is narrow. The evils of black money and tax evasion also have to be reckoned with. The Government is fully committed to come down heavily on tax evaders. At the same time, we must ensure that as far as possible, the tax system itself does not become a source of encouragement for evasion. Simplification and rationalisation of the tax system must, therefore, remain important objectives of our fiscal policy.

15. The Central Public sector enterprises had shown a net profit of Rs. 618 crores in 1982-83. Although a large number of public sector enterprises have continued to show profits in 1983-84, their overall performance has been below expectations. The erosion of profitability was largely due to losses incurred in a few sectors, such as steel and coal. The Government has taken steps to improve their functioning. We must ensure that capital is used more efficiently so that larger resources are available for future expansion.

16. In order to fulfil our social commitments and protect jobs, Government had to take over a large number of sick units and sustain them through injection of fresh resources. While some of them have turned the corner, a large number of them continue to incur losses. The time has come to undertake a careful review of the performance of sick units in the public sector with a view to reducing the drain on our resources. This the Government proposes to do. Economic viability must be the principal test for the survival of an enterprise.

17. The growth of deposits with the banking system in the current year has substantially exceeded their requirements of funds for credit expansion. This has, in the short run, resulted in some excess liquidity with the banking system. In this situation, and in order to mobilise some resources for public investment, it is considered desirable to introduce another financial instrument with broadly the same characteristics as longer term time deposits with banks. Under the scheme, which will be called the "National Deposit Scheme", certificates of deposits with a maturity of four years can be purchased from designated outlets. The investor will have the option to encash these deposits any time after one year. The interest rate will be 10.5 per cent if these deposits are held for four years and 10.9 and 7 per cent if these are held for three, two and one year respectively. Interest from these deposits will be eligible for tax exemption upto the full limit of Rs. 10,000 under Section 80T of the Income-tax Act. The target of receipts under this scheme is Rs. 500 crores over a

period of time. I should clarify that this is a temporary scheme, and will be discontinued after this target is reached or earlier, if monetary developments so warrant.

18. Pursuant to the recommendations of the High Level Committee on financial institutions set up by the Government last year, it has been decided to make certain changes in the "convertibility clause". In view of the increases in capital costs of projects and the investment limit for the delicensed sector, the threshold for exemption from convertibility clause is being raised from the existing level of Rs. 1 crore to Rs. 5 crores.

19. Further, in the case of non-MRTP companies, convertibility clause will not be stipulated where the holding of equity by all financial institutions in such a company exceeds 26 per cent. In the case of MRTP companies/large houses, however, the existing limit of 40 per cent will continue. In order to encourage investment in "No Industry" district there will be complete exemption from convertibility clause in respect of units proposed to be located in these districts. The functioning of nominee directors of institutions on the boards of assisted companies is also being revamped. Detailed guidelines on these and other related aspects are being issued separately.

20. The Industrial Development Bank of India has been providing liberal financing facilities for modernisation of industry. The IDBI's scheme for this purpose was recently extended to all industrial units and assistance under this scheme upto Rs. 4 crores is being provided at a concessional rate of interest of 12.5 per cent. In order to reduce financing costs of modernisation schemes, it has been decided that the rate of interest under the IDBI scheme for loans upto Rs. 4 crores will be reduced to 11.5 per cent until further notice. Weak units will be provided assistance upto this amount at an even lower rate of interest of 10 per cent.

21. As the House is aware, the Government has been giving consideration to the desirability of a change in the financial year. As I informed the House last year, I invited the views of the State Governments on this proposal. The response has been generally favourable. In order to examine suggestions received from State Governments as well as trade and industry, and to work out the modalities for effecting a change in the financial year, I propose to set up an expert committee, which would include representatives of Central Government, State Governments, Reserve Bank of India, Comptroller and Auditor General and some non-official members. This committee will be requested to submit its report by the end of September, 1984.

22. I shall now turn to the Revised Estimates for 1983-84 and the Budget Estimates for 1984-85.

#### Revised Estimates for 1983-84

23. The House will recall that the Central sector Plan outlay for 1983-84 was fixed at Rs. 13,870 crores. This was to be financed to the extent of Rs. 8,390 crores from the budget and Rs. 5,480 crores through the internal and extra-budgetary resources of the public sector enterprises. Despite erosion in the internal resources of certain public sector enterprises, it has been my endeavour to ensure that the total Plan outlay during the year is not adversely affected. The Central Plan outlay in 1983-84 is now estimated at Rs. 14,059 crores. This has been made possible by an increase in the budgetary support by Rs. 1,007 crores over the Budget Estimates.

24. Budgetary support for the Posts and Telegraphs Plan has been increased by Rs. 203 crores. The Railway Plan outlay has been stepped up by Rs. 100 crores with an additional budgetary support of Rs. 54 crores. In the Transport and Communications sectors, I have provided additional funds for Space projects like INSAT, and extension of television coverage. To maintain the progress of the Visakhapatnam Steel Plant, the budget provision has been augmented by

Rs. 250 crores. For Chemicals & Fertilizers, the enhanced allocation of Rs. 133 crores is largely due to the fall in internal resources and change in the pattern of financing. In the Energy sector, coal projects get additional funds of Rs. 30 crores to expedite on-going projects. To improve the capital base of the Industrial Development Bank of India, a special provision of Rs. 139 crores has been made. Rupees 110 crores have been set apart for the new rural landless employment guarantee programme launched during the current year. I have also increased the provision for welfare of scheduled castes/tribes and backward classes and important social sectors like health and family welfare.

25. The Central assistance for States' and Union territories' Plan has been increased by Rs. 392 crores from Rs. 4,462 crores to Rs. 4,854 crores. This includes advance Plan assistance of Rs. 190 crores to States affected by failure of monsoon particularly in the first half of the current year. Additional Plan assistance of Rs. 82 crores has been provided to the State of Assam, a large part of which is for relief and rehabilitation of the riot victims in that State.

26. Utmost care has been taken to contain the non-Plan expenditure. There were, however, certain unavoidable commitments. Additional provision of Rs. 400 crores has been made for ways and means advances to State Governments and Technical Credits under rupee-trade agreements. The short-term loans to States for agricultural inputs have been stepped up by Rs. 110 crores. There is an increase of Rs. 300 crores in loans to State Governments, as their share of small savings will be higher on account of higher collections. The second half of the current year witnessed floods, cyclones and hailstorms in as many as 15 States. An additional non-Plan grant of Rs. 150 crores has been provided for the relief of distress on account of these calamities.

27. Further, I am providing additional non-Plan assistance amounting to Rs. 500 crores to States. I shall refer to this later while dealing with the State Plan outlay for next year. Out of this loan of Rs. 300 crores, an amount of Rs. 400 crores would help the States to clear part of their deficit of 1982-83.

28. The provision for Defence has been increased from Rs. 5,971 crores to Rs. 6,350 crores in the Revised Estimates. The interim relief and bonus sanctioned to Government employees in the current year is estimated to cost about Rs. 280 crores in respect of all the departments of the Government. Subsidy on imported and domestic fertilizers will go up by Rs. 250 crores to Rs. 1,048 crores as the consumer price of fertilisers was reduced in June 1983. During the current year, because of financial difficulties, certain public sector undertakings, particularly Heavy Engineering Corporation, National Textile Corporation and Delhi Transport Corporation, will be requiring larger non-Plan assistance than provided in the Budget Estimates. It has also been decided to extend the subsidy scheme for Calcutta Port and Haldia Channel dredging up to the end of next year.

29. Revised Estimates also include additional provision of Rs. 502 crores for subscription towards our higher quota in the IMF. This, however, will have no net impact on the budget as payments for quota subscriptions are matched by corresponding receipts. Taking these and other variations into account, the non-Plan expenditure in the Revised Estimates is placed at Rs. 34,773 crores against the Budget Estimates of Rs. 21,984 crores.

30. Coming to receipts, the Budget Estimates of receipts from income-tax and customs duties are likely to be achieved. Corporation tax receipts will be higher by Rs. 203 crores due to larger payments by oil companies. Union excise duties are also estimated to be Rs. 85 crores higher mainly due to larger collection of cesses on crude oil and coal. The Centre's tax revenue, after paying the States' share of taxes, is estimated at Rs. 15,700 crores as against the Budget Estimates of Rs. 15,460 crores.

31. Under non-tax revenue, the dividend from Railways is likely to be Rs. 127 crores less than the Budget Estimates. This decrease will, however, be more than offset by increases under other heads and total non-tax revenue in the current year is expected to show an improvement of Rs. 130 crores over the Budget Estimates.

32. Under capital receipts, I am happy to inform the House that the net collections under small savings during the current year may amount to Rs. 2,200 crores against the Budget Estimates of Rs. 1,700 crores. This is a welcome response to the incentives provided for small savings in the current year's budget. The repayment of Technical Credits expected to be Rs. 1,150 crores as against Rs. 800 crores assumed in the Budget. The receipt, net of outgo, will be Rs. 350 crores against the Budget Estimates of Rs. 200 crores.

33. The receipts from special deposits of non-Government provident funds and the like are estimated to be Rs. 190 crores higher than the Budget Estimates. Taking into account the deposits of surplus funds of oil sector, additional recoveries of ways and means and short-term advances to the State Governments and other variations, capital receipts in the current year are estimated at Rs. 15,965 crores as against the Budget Estimates of Rs. 12,656 crores.

34. Total receipts are thus estimated to go up from Rs. 33,250 crores to Rs. 36,929 crores. This will leave a budgetary deficit of Rs. 1695 crores for the current year as against the Budget Estimates of Rs. 1,586 crores. This excludes the special loan assistance of Rs. 400 crores provided to States for clearing their overdrafts at the end of the previous year 1982-83. I am sure the House will agree that despite unavoidable budgetary pressures, we have been able to keep the deficit within prudent limits.

#### Budget Estimates for 1984-85

35. Hon'ble Members will recall that when our Government took office in January 1980, an important task before us was to revitalise the planning process and to give a new thrust to the programmes of development. I am happy to say that, in the last four years, we have been able to achieve an unprecedented increase in the tempo of public investment.

36. For 1984-85, the approved Plan outlay of the Centre, States and Union territories will be Rs. 30,132 crores as compared to Rs. 25,480 crores in 1983-84. The Central Plan outlay for 1984-85 is Rs. 17,351 crores, which represents a step up of 25 per cent over the approved Plan outlay of Rs. 13,870 crores in 1983-84.

37. The Plan outlay for the States and Union territories is placed at Rs. 12,781 crores as compared with the final approved outlay of Rs. 11,678 crores in 1983-84. Central assistance for the Plans of States and Union territories will be Rs. 5,050 crores as against Rs. 4,462 crores in 1983-84 Budget Estimates, representing an increase of 13.2 per cent over the allocation made for the current year.

38. Within this aggregate, Plans of individual States show a varied picture. Some States have managed their finances well; they have been able to raise additional resources and effectively utilise these to implement adequately sized plans, providing development and growth to their people. Unfortunately, some States, for reasons of their own, have used their resources for various other purposes; they have not invested their resources, including additional resources mobilised, for development and have also resorted to large overdrafts on the RBI.

39. With a view to assisting even such States, various facilities and opportunities were provided from time to time. At the beginning of the Sixth Plan itself, recovery of outstanding advance assistance amounting to Rs. 1412 crores was postponed. This was done to enable States to start with a clean slate. However, State overdrafts again grew, and in June 1982, I decided to clear States' closing deficits of the previous year with a medium term loan of Rs. 1743 crores. RBI also doubled the ways and means limits available to the States. Again last year, while presenting the budget, I announced an increased level of Central assistance. All these measures were taken primarily to assist States to readjust their financial affairs and to be able to implement State Plans of adequate size.

40. Unfortunately, despite these measures, some States continued to rely heavily on overdrafts even after March 1982. Their proposed deficits at the end of March 1984

would have harshly affected their Plan sizes if these deficits were adjusted against next year's Plan, as per normal practice. In considering the ways of overcoming this problem, I have found myself in a predicament. On the one hand, no Finance Minister of the country can remain unconcerned about the size of a State's Plan. On the other hand, if assistance is extended to defaulting States, the well-managed States can legitimately complain that they have not got their just rewards from the Centre for their better performance.

41. In the past few weeks, discussions were again held with the Chief Ministers of States whose overdrafts with the RBI were high. Several State Governments have agreed to take the necessary measures to improve their financial position and to reduce their reliance on overdraft. On my part, I have agreed to take further steps to provide additional assistance to States in order to protect their Plans as far as possible. In doing so, I have been particularly conscious of the need to keep up the momentum of anti-poverty programmes. Central assistance is also being further increased. With this, the aggregate assistance during the Plan period will amount to Rs. 17,790 crores as against Rs. 15,350 crores envisaged in the Plan document. Further, as I mentioned earlier, I have made an additional provision of Rs. 500 crores in the Revised Estimates for 1983-84. This special assistance would enable these States to clear part of their overdrafts with the RBI. States have also been informed that closing deficits, upto the permissible ways and means limits from the RBI will not be adjusted from next year's Plan resources.

42. For those States who have managed their finances well, I am working out a suitable scheme to provide some additional assistance to them in 1984-85. This is only just and appropriate.

43. Mr. Speaker, Sir, I am sure that the House will agree with me that, despite severe resource constraints of its own, the Central Government has done the maximum that it can to solve the States' problems. The rest, however, is upto them.

44. Altogether, in the Sixth Plan period, the public sector Plan at current prices will be over Rs. 110,000 crores. This compares with Plan expenditure of Rs. 46,700 crores in the preceding five years, which, of course, include three years of "non-Plan" launched by the previous Government. In real terms too, the Sixth Plan will constitute a massive increase over the outlays provided for in any previous Plan. This, Mr. Speaker, is the measure of achievement of this Government in accelerating the pace of development in the current Plan period.

45. In the last four years, the present Government introduced a number of schemes for the benefit of the weaker sections of the society, particularly in the rural areas. These include the Integrated Rural Development Programme, the National Rural Employment Programme and two new programmes announced by the Prime Minister on 15th August, 1983, namely, the Rural Landless Employment Guarantee Programme and the scheme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. Each of these programmes is designed to create opportunities for employment and income generation for particular target groups, while also creating productive assets.

46. In formulating the next year's Plan we have provided the maximum support to these and other programmes that benefit the rural poor directly. The total allocation for various programmes of the Ministry of Rural Development would be Rs. 932 crores, which is nearly double the amount of Rs. 480 crores provided in 1983-84. For the IRDP an allocation of Rs. 216 crores is being provided, which is to be matched by the States. The number of beneficiaries under the programme in 1984-85 is estimated at over 3 million. For the NREP, the outlay for 1984-85 is Rs. 230 crores which will again be matched by the States.

47. The allocation for Rural Landless Employment Guarantee Programme, which seeks to provide employment for 100 days in a year to at least one member of every rural landless family, is being stepped up to Rs. 400 crores in 1984-85 as against a provision of Rs. 100 crores in 1983-84. This, together with the NREP, will provide 550 million man-days of work in rural areas in 1984-85. An allocation of Rs. 25

crores is being made for the programme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. As the House is aware, the budgetary provision under this programme will be used as capital subsidy against loans to be given by banks. I may add that for these two new programmes, depending on the progress of expenditure, more funds will be provided during the course of the year as necessary.

48. In the Plan for 1984-85, Rs. 243 crores have been earmarked for the accelerated rural water supply programme. The States on their part are expected to provide Rs. 364 crores for this purpose under the minimum needs programme. Over 50,000 problem villages are expected to be provided with drinking water facilities during 1984-85.

49. The programme for integrated child development services is an important part of our efforts to help women and children in the backward areas, urban slums and tribal areas of our country. This programme is already in operation in 820 blocks. By the end of 1984, the scheme will become fully operational in all 1000 identified blocks. A provision of Rs. 36 crores has been made for this scheme. A total allocation of Rs. 78 crores is being provided for various schemes of the Department of Social Welfare in 1984-85.

50. The provision in the Central Plan for the various programmes benefiting the scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes has been increased to Rs. 209 crores in 1984-85 compared to Rs. 176 crores only in 1983-84. Plan outlay for the programmes in education and culture has been substantially stepped up to Rs. 204 crores in 1984-85 as against Rs. 155 crores in 1983-84. Likewise, the Plan outlay for health and family welfare programmes has also been stepped up by nearly 32 per cent from Rs. 460 crores in 1983-84 to Rs. 605 crores in 1984-85. The family welfare programmes will cover an additional 20 million persons.

51. These and other socio-economic priorities of the Government are reflected in the 20-Point Programme which is being vigorously implemented. The total amount allocated to the Programme in the Central Plan is Rs. 4038 crores, which is an increase of about 47 per cent over the current year's provision. Inclusive of the outlays to be provided by the States and Union territories, the total provision for the 20-Point Programme will be Rs. 11,858 crores, representing nearly 40 per cent of the total annual Plan outlay of the Centre States and Union territories.

52. An important source of strength for the economy has been the tremendous strides made in the agricultural sector. The next year's Plan will continue the high priority given by the present Government to the development of this sector. Thus, the total outlay for the various programmes of the Ministry of Agriculture will be Rs. 758 crores compared to Rs. 556 crores in the current financial year. The outlay includes Rs. 38 crores for the National Oilseeds Development Project which together with the on-going programmes visualises an additional production of 9.4 lakh tonnes during 1984-85 itself.

53. To further strengthen the country's infra-structure, higher allocations are being provided for power, coal, railways and ports. The total provision for various power projects adds to Rs. 1764 crores, which represents a 44 per cent increase over 1983-84. The allocation for projects of the Department of Coal is Rs. 1310 crores as against Rs. 1076 crores in 1983-84, and the target for coal production is 152 million tonnes in 1984-85. The provision for the Railways in 1984-85 is Rs. 1650 crores, which is 23 per cent higher than the current year. It is expected that the revenue earning traffic to be carried by the Railways will increase to 245 million tonnes in 1984-85. An allocation of Rs. 201 crores is being made for the development of ports, including Rs. 27 crores for the deepening of the Madras harbour.

54. An outlay of Rs. 3127 crores is being provided for petroleum. This includes a sum of Rs. 2685 crores for the programmes of exploration and production, and Rs. 443 crores for the various schemes of refining and marketing. The target for production of crude oil in 1984-85 is about

30 million tonnes. A provision of Rs. 200 crores is also being made for a gas pipeline project for supply of Bassein gas to new fertilizer projects to be set up at Bijapur, Jagdishpur, Aonla, Babrala, Shahjahanpur and Sawai Madhopur.

55. Higher allocations have been provided for steel, non-ferrous metals, paper, cement and several other sectors, which are important for country's industrial development. I would also like to draw the attention of the House to the programmes for the development of science and technology, conservation of natural resources, and improvement of the environment in the Plan for 1984-85. The successful positioning of INSAT-1B in a geosynchronous orbit in August last testifies to the excellent work done by our scientists, engineers and technicians. It is also a matter of pride to us that India has joined a select group of countries which have permanent scientific stations in the Antarctica. India has also achieved the distinction of being the only developing country to be given the status of 'pioneer investor' by the Convention on the Law of the Sea, giving us the right to exploit the mineral resources of the deep sea beds.

56. Finally, I should mention that the incentive schemes for better performance in selected areas, initiated in 1983-84, will continue in 1984-85 also. As the House is aware, these schemes are designed to improve the functioning of the electricity boards, and provide further impetus to the programmes for small and marginal farmers, rural water supply schemes, environmental improvement in urban slums, construction of field channels in command area development projects, and adult education for women and elementary education for girls. A lumpsum provision of Rs. 200 crores is being made for this purpose. Let the Hon'ble Members take me to be a magician, who can do so much with so little. I hasten to clarify that the incentive scheme is designed to provide additional resources linked to performance for specified schemes. There are, of course, also separate substantial allocations for each of these schemes.

57. I have only briefly touched upon the main priorities and objectives of the Annual Plan for 1984-85. Further details are available in the budget documents.

58. In order to provide the maximum possible outlay for the Plan, I have taken special care to ensure that non-Plan expenditure is kept at the minimum. However, certain increases are necessary and unavoidable. I should also add that the estimates of receipts from and payments to State Governments take into account the recommendations contained in the interim report of the Eighth Finance Commission. I have already kept the House informed of this. The final report of the Commission is now expected by the end of April, 1984.

59. I have provided Rs. 6800 crores for Defence expenditure next year against the Revised Estimates of Rs. 6350 crores. I am sure the House will agree that the requirements for Defence have to be met fully to protect the security of the country. Interest payments next year are estimated at Rs. 5600 crores against Rs. 4850 crores in the current year. The borrowings are largely for financing our developmental efforts, and the increase is due to the success of our policies for mobilising savings. A provision of Rs. 850 crores has been made for food subsidy. The requirement for subsidy on indigenous and imported fertilizers is placed at Rs. 1080 crores. Export promotion and market development have been allocated Rs. 530 crores.

60. A lumpsum provision of Rs. 300 crores has been made in 1984-85 for payment of additional instalment of dearness allowance, pensionary relief, etc. to Central Government employees. Including these and, inter alia, provisions which are in the nature of adjustments, total non-Plan expenditure in 1984-85 is estimated at Rs. 26,066 crores against Rs. 24,773 crores in Revised Estimates for 1983-84.

61. Turning to receipts in 1984-85 the gross tax revenues at existing levels of taxation are estimated at Rs. 22,993 crores compared with Rs. 20,946 crores in the Revised Estimates. The States' share of taxes in 1984-85 is estimated at Rs. 5739 crores as against Rs. 5246 crores in the current

year, which is an increase of nearly Rs. 500 crores. The net tax revenues of the Centre will thus be Rs. 17,254 crores compared with Rs. 15,700 crores in the current year. The dividend from Railways and Posts and Telegraphs will be higher by Rs. 106 crores than the Revised Estimates for 1983-84. Interest receipts and repayment of loans by public sector undertakings and State Governments will also be higher.

62. Receipts from market loans are placed at Rs. 4100 crores against Rs. 4000 crores in the current year. Small savings collections are estimated at Rs. 2400 crores against Rs. 2200 crores in the current year. External assistance net of repayments is estimated at Rs. 2089 crores compared with Rs. 1902 crores. Next year's Budget also includes a receipt of Rs. 200 crores from the National Deposit Scheme to which I have referred in the earlier part of my speech. Taking into account these and other variations in receipts, the total receipts in 1984-85 are estimated at Rs. 40,501 crores. These receipts include the effect of the changes in fare and freight rates of the Railways. The total expenditure is placed at Rs. 42,536 crores. The overall budgetary gap at existing rates of taxation will thus be Rs. 2035 crores.

63. I have taxed the patience of the House enough. Let me now turn to other tax proposals.

#### (PART B)

64. In framing these proposals, I have tried to take into account the realities of the economic situation to which I referred at the beginning of my speech. While doing so, I hope I have not been entirely unmindful of a certain forthcoming event which is of importance to all of us in this Parliament.

65. Mr. Speaker, Sir, my first proposal relates to the non-corporate income-tax sector. I propose to revise substantially the entire rate structure relating to personal taxation. The present rate of tax in the first slab of taxable income ranging from Rs. 15,001 to Rs. 20,000 is 25 per cent. The House will recall that this rate was brought down last year from the then prevailing level of 30 per cent. I now propose to reduce this rate further to 20 per cent. Relief has been allowed at all income levels above Rs. 20,000 also. The maximum marginal rate of tax on incomes over Rs. 1 lakh is being reduced from 60 per cent to 55 per cent. The new rates in some illustrative slabs will be as follows : in the income slab of Rs. 25,001 to Rs. 30,000, the new rate will be Rs. 30 per cent as against 35 per cent at present; in the income slab of Rs. 50,001 to Rs. 60,000, the new rate will be 45 per cent as against 50 per cent at present; and in the income slab of Rs. 70,001 to Rs. 80,000 the new rate will be 58 per cent as against 55 per cent at present.

66. The above proposal will provide relief at all levels of incomes. Even with the increase in the standard deduction introduced last year, I expect this measure will provide substantial relief in particular to the fixed income groups. The revised tax schedule will provide a relief in tax of Rs. 281 to a taxpayer with an income of Rs. 20,000, which is 20 per cent of the tax payable by him earlier. For an income level of Rs. 30,000, the relief will be Rs. 844 or 16.7 per cent of the tax payable under the old structure, and at income level of Rs. 50,000, this relief will be 10 per cent of the tax payable.

67. The loss of revenue in the proposed rate schedule, assuming no change in the number of taxpayers and the assessed incomes in different income slabs, is calculated at Rs. 180 crores. However, lowering of the tax rates should normally be expected to lead to an increase in the coverage of taxpayers in different tax slabs and also better tax compliance. Taking these factors into account, I have assumed a net revenue loss of Rs. 59 crores only. This loss is entirely attributable to tax relief provided to the fixed income groups. As far as business and professional incomes are concerned, I have assumed that the reduction in the rates will encourage better compliance and reporting and that this will partly cover the revenue loss.

68. This proposal, Mr. Speaker, Sir, in a way continues the tax rationalisation programme that was started by my Party in 1974; carried forward in 1976 and further reinforced after we came back to power in 1980. The present

tax structure has also been brought down to a level which I regard as realistic and entirely appropriate. I hope this measure will have a salutary effect on our tax culture and will induce the maximum number of taxpayers to come forward and voluntarily declare their true incomes.

69. At the same time, it is necessary to simplify tax administration and make it more responsive to the needs of the taxpayers. One essential feature would be the effort to complete assessments within the shortest possible time. As the Hon'ble Members are aware, the scope of the summary assessment scheme covers incomes upto Rs. 1 lakh. Only a percentage of cases with incomes in this range is being scrutinised, the selection of such cases being on random sampling basis. The target for 1983-84 is to complete 85 per cent of the summary assessments workload. I have instructed the Income Tax Department to further speed up the assessments.

70. For some years, the Income-tax Act has contained provisions empowering the Central Government to acquire immoveable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000. This power is exercisable in situations where the declared consideration for transfer of the property is less than the fair market value of the property. To eliminate unproductive work in handling a large number of relatively small value cases and also taking into account the rise in market prices I have modified the provision to say that this power will be exercised only in cases where the fair market value exceeds Rs. 50,000. As a further simplification it is being provided that the prescribed statement will have to be filed before the registering officer only in cases where the value of consideration for the transfer exceeds Rs. 25,000 as against Rs. 10,000 at present.

71. With the reduction in rates and expeditious disposal of assessments, I believe there can now be no excuse for any leniency to be shown to those who abuse our laws. Such cases will necessarily have to be dealt with severely. In order to discourage tax avoidance and tax evasion, I am also introducing some further measures. In all cases where the annual turnover exceeds Rs. 20 lakhs or where the gross receipts in a profession exceed Rs. 10 lakhs, I am providing for a compulsory audit of accounts. This is intended to ensure that the books of account and other records are properly maintained and faithfully reflect the true income of the taxpayer. I am also proposing that loans or deposits of Rs. 10,000 or more shall be taken or accepted only by crossed cheque or bank draft.

72. I find that the existing provisions of the Income-tax Act provide that no suit to enforce any right relating to any property held benami can be instituted in any court by a person claiming to be the legal owner unless he has declared the income from such property in any return of income or the value of such property in any return of net wealth or furnished a notice in this behalf in the prescribed form to the Income-tax Officer. Such return or notice can at present be given at any time before the suit is filed. With a view to curbing the practice of benami holding of property I am proposing that it will henceforth be obligatory in all cases to give notice to the Commissioner of Income-tax in the prescribed form within one year of the acquisition of the property. This amendment will enable the Department to initiate appropriate action in respect of such benami acquisition of property well before the limitation for such action expires.

73. Having dealt with the non-corporate sector, I now turn my attention to the corporate sector. The tax rates for this sector are not being changed. I am however providing one facility. Last year, while raising the surcharge payable by companies from 2.5 per cent to 5 per cent, I had given companies the option to make deposits of the additional surcharge with the Industrial Development Bank of India. I am now further providing that companies can henceforth exercise this option in respect of the entire amount of the surcharge payable by them. These resources will flow back to the corporate sector, and will be available for modernisation. In the earlier part of my speech, I have already referred to the decision to reduce the interest rates on loans upto Rs. 4 crores being extended by IDBI under the soft loan scheme.

74. Representations had been received from various quarters that the ceiling on the deductible amount of managerial

remuneration as contained in the Income-tax Act is low and should be raised. I am glad to inform the House that having regard to the changes in the managerial remuneration introduced by the Department of Company Affairs, I am also raising the ceiling limits for managerial salaries from Rs. 5,000 to Rs. 7,500 per month. The ceiling in respect of perquisites will however remain unchanged.

75. Some relaxations are also being provided to those engaged in the business of growing and manufacturing tea. The existing provisions provide exemption from tax only in respect of subsidy received for replantation or replacement of tea business. I am extending this tax exemption to cover subsidy received for other approved schemes relating to rejuvenation and consolidation of areas. I hope this measure will further lend support to our scheme for increasing production of tea.

76. My next proposal, I believe, will be welcomed by a large number of people. Investors presently can receive dividends and interest on debentures without deduction of tax at source, if they furnish an exemption certificate from the Income-tax Officer or alternative file a declaration to the effect that their income for the year is below the exemption limit. To reduce paper work and avoid inconvenience to small investors, I propose to provide that widely-held companies may, henceforth, pay interest on debentures and dividend income upto Rs. 1,000 without deduction of tax at source provided that the payment is made by an account payee cheque or a bank draft.

77. Mr. Speaker, Sir. I notice that certain provisions of tax laws are being misused by a section of the taxpayers. I had occasion last year to deal at some length with taxation of charitable and religious trusts and institutions. I find that some of these trusts and institutions are trying to circumvent the investment pattern for trust funds laid down by the Finance Act, 1983. It is necessary to ensure that all such trusts and institutions strictly conform to the prescribed investment pattern and that such income or property is not used for providing benefit to the settlors, trustees, etc. I, therefore, propose to provide for taxation of the income of defaulting trusts and institutions at the maximum marginal rate of income-tax.

78. While on this subject, I would like to refer to a tendency noticed to create private trusts which carry on business. To curb such practice, I propose to provide that where such trusts have profits and gains of business, the entire income of the trust will be charged to tax at the maximum marginal rate, an exception being made only in the cases where the trust is created by will for dependant relatives.

79. Another undesirable practice noticed is the tendency of some corporate bodies to make large contributions to the so-called welfare funds. I further understand that utilisation of these funds is discretionary and subject to no discipline. I am, therefore, providing that deduction will be available only in respect of contributions to such funds as are established under statute or an approved provident fund, superannuation fund or gratuity fund. I am making this change with retrospective effect to avoid unnecessary litigation.

80. Last year, I liberalised the scheme related to export turnover. I propose to continue it and watch its operation for a longer period of time.

81. Last year, I had also referred to a large variety of exemptions and deductions that had been built into our tax system over time. While each deduction by itself may have its own merits, the aggregate effect was to complicate the tax administration and to provide loopholes for tax avoidance or tax evasion, as also for litigation. I had, therefore, initiated a process of review and, where necessary, doing away with concessions which had outlived their utility. I intend to carry this process further.

82. Our experience has shown that an expenditure related concession leads to a tendency to inflate expenditure and hence it should have no place in our tax system. Therefore, I propose to withdraw all weighted deductions as are available under the different provisions. The expenditure actually incurred will of course, continue to qualify for deduction. Only the benefit of weightage will no longer be available.

83. I am also withdrawing the exemptions available under sections 33B, 35C, 80CC, 80D and 80E of the Income-tax Act. These deductions, notwithstanding their apparent laudable objectives have either been open to misuse or have benefitted only a few. The revenue involved is marginal. I am also reducing the quantum of exemption available under Sections 80M, 80N and 80-O.

84. Now, I intend to announce a few concessions in respect of the Wealth-tax Act. Hon'ble Members, I am sure, will be happy to hear that the monetary ceiling of exemption in respect of one house owned by a taxpayer is being increased from the present level of Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs. This is being done to take into account the increase in market value. I am also proposing to raise the exemption limit in respect of specified financial assets from the present level of Rs. 1,65,000 to Rs. 2,65,000. Together with separate exemption of Rs. 35,000 available in respect of units of the Unit Trust of India and proposed to be extended to deposits under the National Deposit Scheme, the aggregate exemption in respect of the value of specified financial assets will rise to Rs. 3 lakhs as against the present ceiling of Rs. 2 lakhs. Hon'ble Members would recall that in the earlier part of my speech, I had referred to the success in mobilising savings in the form of financial assets; I hope that this change will give further impetus to it.

85. The other changes proposed by me in respect of direct taxes are of relatively minor nature and I would no like to take the valuable time of this House by elaborating them.

86. After adjustment of the gain to revenue on account of withdrawal or modification of certain concession, my proposal in regard to income-tax will lead to a net loss of Rs. 75 crores, of which the loss to the Centre would be Rs. 36.22 crores and the loss of the States would be Rs. 38.68 crores.

87. Mr. Speaker, Sir, I shall now deal with my proposals in the area of indirect taxes. Here my main objective has been to provide further impetus to the growth of Indian industry through tariff adjustments and substantial relief in excise duties in carefully selected areas. I have also kept in view the need to reduce prices of certain items for consumers and contain the rate of inflation in the economy. I am sure the Hon'ble Members will not grudge, if in doing so, I have also taken a little care of Government revenues.

88. My principal proposal relating to customs duties is with regard to auxiliary duty of customs. The levy imposed on an annual basis since the 1973 Budget is proposed to be continued upto the 31st of March, 1985. I also propose to raise, with certain exceptions, the present effective rates by 5 percentage points. I am excluding from the proposed increase essential items like fertilizers, bulk petroleum products such as kerosene and high speed diesel oil, and also newsprint. Fuller details of these proposals are available in the Budget papers. This proposal is expected to yield an additional revenue of Rs. 241.73 crores in a full year.

89. The present customs duty on crude petroleum of Rs. 9.50 per metric tonne (which is being collected by way of auxiliary duty) was fixed in 1973. Without affecting the domestic prices of petroleum products, I propose to raise the duty on crude to Rs. 100 per metric tonne. The revenue gain from this measure will be Rs. 132.76 crores. This duty increase is to be absorbed by the oil companies without their having to raise consumer prices on this account.

90. The current rates of import duties on iron and steel items were fixed a few years back and they are now out of line with the requirements of indigenous industry. I propose to raise the basic customs duty on different items of iron and steel (other than stainless steel) by 5 percentage points or 19 percentage points, depending upon the existing rates of duties. I also propose to levy a total customs duty of 20 percent ad valorem on stainless steel melting scrap, which is presently exempt from customs duty. These measures are expected to yield an additional revenue of Rs. 84.20 crores.

91. I also propose to increase the import on duty zip fasteners and parts thereof, magnetic tape and petroleum specialities, namely petroleum jelly, sodium petroleum sulfonate and liquid paraffin. Details of the proposals are available

in the Budget papers. The revenue gain in these proposals would be of the order of Rs. 5.32 crores.

92. In order to promote exports in the important sector of gems and jewellery, customs duties leviable on a number of gem and jewellery processing and manufacturing machines are proposed to be reduced from the respective existing rates to 40 per cent ad valorem. The gem processing machines would enable significant reduction in processing losses and also improve overall quality and productivity. Similarly, I also propose to reduce customs duties on **specified machines** used in packaging of food articles as well as by meat and food processing industries from the respective existing rates to 40 per cent ad valorem. This measure is expected to encourage export of food items in value-added form and also in consumer packs instead of in bulk. The revenue sacrifice involved in the above proposals is of the order of Rs. 5.24 crores.

93. With the advancement in machine tool technology, CNC machines are progressively replacing conventional machine tools due to their higher productivity and accuracy. To enable the indigenous machine tool manufacturers to offer CNC machine tools on competitive terms, I propose to reduce the customs duty on CNC systems to 35 per cent. The revenue sacrifice is of the order of Rs. 0.82 crore.

94. To enable the paper industry to obtain its raw materials at reasonable prices and to relieve the pressure on our forest resources, I propose to totally exempt from customs duties wood chips for making pulp for the manufacture of paper or paper board. On similar considerations, I propose to reduce the duty on wood pulp imported for manufacture of paper from the existing levels to 30 per cent. These measures involve revenue sacrifice of the order of Rs. 1.10 crores.

95. Certain changes in the provisions of the Customs Act, 1962, relating to warehousing, etc. and in the Customs Tariff Act, 1975 are also proposed. The details of these proposals have been given in the Budget papers.

96. Sir, coming now to my proposals in respect of excise duties, my main objectives are to minimise the effects of inflation, lessen scope for tax avoidance and evasion, give a boost to selected industries suffering from demand recession, and ensure better utilisation of the capacity and investment already created.

97. I propose to continue upto 31st March, 1985 the levy of special excise duties at the existing rates and with the existing exemptions.

98. My first proposal for relief is in respect of khandsari sugar. I propose to fully exempt khandsari sugar from the levy of excise duty. I am taking this measure in view of the labour-intensive character of this industry, and to provide further opportunity for growth of employment in this industry. The abolition of excise duty will also help this industry to pay better price to cane growers, and, will give relief to a large number of khandsari units located in far-flung rural areas. The revenue sacrifice involved in this proposal is Rs. 16.42 crores. Khandsari, I am told, is also better for health. If as a result of this measure, the health of the nation improves, I hope the credit will flow to me and not to my distinguished colleague, the Health Minister!

99. Hon'ble Members would recall that excise duty was levied on electricity as a revenue measure in the 1978 Budget. The net proceeds from the duty collected on electricity are wholly distributed to the States. It is proposed to abolish the excise duty on electricity leaving it to the State Governments to tap this source, to whatever extent and in whatever manner they like. This will give to the States one more area for resource mobilisation. To give the States some time to take appropriate action, this abolition will be effective from 1st October, 1984.

100. I also propose to provide substantial relief to the textile industry with a view to making cloth cheaper. Hon'ble Members may recall that in the 1982 and 1983 Budgets, excise duty was reduced to encourage the production of blends with the desirable proportions of polyester. Such fabrics are becoming increasingly popular with the people.

As a further measure of relief in this area and with the overall objective of making such fabrics available at lower prices, I propose to reduce the total excise duty on polyester-cotton blended yarn containing more than 40 per cent but less than 70 per cent polyester to Rs. 5 per kg. The existing rates of duty on such yarn vary generally from Rs. 7.5 per kg. to Rs. 22.5 per kg. depending on the extent of polyester-cotton mix. Under my proposal all blends over 40 per cent but below 70 per cent of polyester will pay the same reduced rate of duty. For similar blends of polyester and viscose, the excise duty will get reduced to Rs. 10 per kg. from the present rates which generally vary from Rs. 11.25 per kg. to Rs. 22.50 per kg. The revenue sacrifice on these accounts is estimated at Rs. 33.25 crores in a full year.

101. Blended fabrics have also received my attention. The excise duty on polyester-cotton blended fabrics containing more than 40 per cent but less than 70 per cent polyester will be reduced to 2 per cent ad valorem. The incidence of duty on such fabrics at present varies from 7.5 per cent to 17.8 per cent ad valorem. This concession would cost the exchequer Rs. 26.50 crores in a full year. I also propose that this duty at 2 per cent ad valorem be collected as additional excise duty in lieu of sales tax. As Hon'ble Members are no doubt aware, proceeds of additional excise duties on textiles go to the States.

102. These changes in the duty structure on polyester-cotton blended yarn and polyester-cotton blended fabrics will for a 67 : 33 blend, reduce the duty incidence by about Rs. 3.30 per square metre on a fabric carrying a wholesale price of about Rs. 25 per square metre, and a retail price of Rs. 35 to 40 per square metre. This duty reduction will enable the industry to sell such fabrics at reduced prices.

103. I also propose to provide relief on cotton fabrics which still constitute a major share of the total production of cloth in the country. I propose to reduce excise duty on cotton fabrics of less than 51 counts and of assessable value not exceeding Rs. 5 per square metre. Such fabrics at present pay duty of excise at rates varying from 2.38 per cent to 3.56 per cent ad valorem in the case of composite mills. Concessional rates of duty are allowed for independent processors processing powerloom and handloom fabrics. I propose to fully exempt handloom and powerloom fabrics of the above varieties processed by independent processors. The rate of duty for composite mill fabrics is also being reduced to 1 per cent ad valorem retaining more or less the present differential between the independent processors and the composite mills. This duty would be in the nature of additional excise duty in lieu of sales tax and will entirely go to the States. Such fabrics are mostly consumed by the weaker sections of society. The benefits of the reduction should become available to them in the form of lower prices. This proposal on cotton fabrics would entail a revenue sacrifice of Rs. 28.40 crores.

104. I hope, my proposals would also help the textile industry. The industry should benefit through increased demand that lower prices would generate.

105. Cotton yarn and cellulosic spun yarn in the form of cross reel hanks are finding increasing use in the handloom sector. In the Handloom Year, I propose to reduce the duty incidence on such yarn supplied to registered Handloom Cooperative Societies or to organisations set up or approved for the development of handlooms by about 50 per cent. This would involve a loss of Rs. 3 crores to the exchequer in a full year.

106. In order to recoup some of the revenue loss flowing from the above package of measures in respect of the textile industry, I propose to increase the incidence of additional excise duty in lieu of sales tax from 7.5 per cent to 10 per cent on man-made fabrics of assessable value exceeding Rs. 25 per square metre. This increase will not apply to those blended fabrics in respect of which duty is being reduced. The impact will be on costlier fabrics which are consumed mainly by the more affluent sections of society. They should not mind this. On this account, the exchequer will gain by Rs. 27 Crores in a full year and this, too, would accrue entirely to the States.

107. I also propose to reduce the duty on shoddy blankets and other similar blankets made from shoddy yarn processed by composite mills by about 7 per cent. Such shoddy blankets if processed by independent processors will be wholly exempt. The revenue loss on this account would be Rs. 1 crore in a full year.

108. Another industry needing urgent attention is the paper industry. This industry has been passing through a difficult phase troubled by rising cost of raw materials and other inputs. My proposals aim at encouraging the production of paper and paper board and preserving scarce natural forest resources. I have already referred to the proposed exemption from customs duty on import of wood chips and wood pulp for paper making. As a further measure of relief, I propose to reduce the basic excise duty on printing and writing paper and also kraft paper produced by large paper mills by Rs. 425 per metric tonne, and corresponding concessions are being given on the duty leviable on such paper when unconventional raw materials are used in their manufacture. Simultaneously, the range of permissible unconventional raw material is being expanded.

109. No concession for use of unconventional raw material is presently available in the case of paper boards. I propose to reduce the basic excise duty payable on paper boards manufactured from at least 50 per cent unconventional raw materials from the present general level of 10 per cent ad valorem + Rs. 1430 per metric tonne to Rs. 560, Rs. 900 or Rs. 1120 per metric tonne depending on whether the clearances of paper and paper board from such paper mills in the preceding financial year did not exceed 3,000 tonnes, 7,500 tonnes or 16,500 tonnes respectively. For larger paper mills using unconventional raw materials, the rate of basic excise duty on paper boards is being reduced to 7 per cent ad valorem + Rs. 925 per metric tonne.

110. My proposals relating to the paper industry would entail a loss of Rs. 33 crores in excise duties in a full year. Along with the customs duty exemptions on import of wood chips and wood pulp, this package is expected to provide substantial fiscal support to the development of indigenous paper industry and improve the availability of paper at reasonable prices.

111. Hon'ble Members may recall that certain time bound concessions were given in October, 1983, in respect of certain specified commodities. Having regard to the industry's response to that measure which was intended to stimulate production by generating incremental demand, I propose to continue the concession for one year with certain modifications.

112. In the case of commercial vehicles and three-axled vehicles, the concession will be continued but the extent of duty concession granted in October, 1983 is being reduced by 2-1/2 percentage points. I propose to remove some 100,000 light commercial vehicles from the purview of the exemption in order to establish parity among all models of such vehicles in the matter of the rate of excise duty. These proposals would entail a revenue loss of Rs. 45 crores in a full year.

113. I propose to continue the concessions in the case of refrigerators, deep freezers and parts of refrigerating appliances etc., storage batteries and domestic electrical appliances. The total revenue sacrifice on these items would be to the tune of Rs. 19 crores.

114. In the case of tyres for buses and trucks and tyres for use off-the-road, I do not propose to continue the concession granted to October, 1983 as there is no further case for this concession in view of the price increases announced by this industry. However, as a measure of rationalisation and in order to reduce scope for tax evasion, I propose to switch over by and large to a system of specific rates of duties from the ad valorem rates.

115. Production of china and porcelain tableware over the last few years has been showing signs of stagnation and the capacity utilisation has been declining. With a view to providing relief to the industry, I propose to reduce the basic excise duty from 30 per cent to 15 per cent on these items. This would entail a revenue loss of Rs. 15 crores.

116. With summer not very far away, I would like to help the Hon'ble Members in keeping their tempers cool. I propose to reduce basic excise duty on table fans from 10 per cent to 5 per cent and on ceiling fans of a diameter not exceeding 107 cms from 15 per cent to 7.5 per cent. I also propose to reduce the basic excise duty on evaporative type of coolers, including desert coolers, from 40 per cent to 30 per cent ad valorem. These proposals would involve a revenue sacrifice of Rs. 5.10 crores.

117. As a rationalisation measure, I propose to reduce the basic duty on winding wires from 10 per cent to 5 per cent and increase the basic duty on copper wire rods by Rs. 1300 per metric tonne. On an overall basis, these changes will neither result in a loss nor gain in revenue.

118. As Hon'ble Members will remember, many reputed artists had published an appeal inviting our attention to piracy. As I "just can't write these names off" I propose to exempt sound-recorded cassettes wholly from excise duty. In view of the upward revision of customs duty on magnetic tapes, the revenue loss on this account is expected, by and large, to be made-up.

119. As a general measure of relief I propose to fully exempt laundry soap manufactured by KVIC units and to reduce basic excise duty from 10 per cent to 5 per cent on certain mass consumption items such as imitation jewellery, stainless steel utensils, glass chimneys for lanterns, high efficient wood burning stoves, umbrellas and saccharine. The revenue sacrifice involved in these concessions is Rs. 113 crores.

120. Hon'ble Members may recall that an excise duty relief scheme to encourage higher production is in operation for the past two years. I propose to continue the scheme for one more year.

121. Hon'ble Members would also recall that in the last Budget, I had rationalised the tariff relating to iron and steel items. This year, I have undertaken a similar exercise in respect of non-ferrous metals. The tariff entries are being revised on a more scientific basis. These changes as in last year would be brought into effect from a subsequent date. Till then, the present effective rates of duty would continue.

122. I propose to increase the additional excise duty in respect of cigarettes. The present ratio between basic excise duty and additional excise duty is being altered to 1.75 : 1. This measure will result in the transfer of Rs. 42.89 crores from the basic excise duty account to the additional excise duty account in the next financial year, and thus increase the accrual to the States. There will be a corresponding reduction in the amount allocated to basic excise duty. The total incidence of excise duties on cigarettes will remain unaltered.

123. There are some other minor proposals which do not have much revenue significance. These include readjustment of duties in some cases and deletion of some tariff items which have remained fully exempted for a long time.

124. In the light of the experience gained in the working of the Income Tax Appellate Tribunal and the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, some amendments are proposed to be carried out in the laws relating to them. These are mainly of an administrative nature. I do not propose to take the time of the House over these proposals.

125. Mr. Speaker, Sir, with the phenomenal increase in central excise revenue from about Rs. 100 crores in 1953-54 to about Rs. 10,100 crores in 1983-84, the Central Excise Tariff has also substantially grown. I think, it is time to make a comprehensive review of the tariff as it has developed over the last three decades with a view to rationalising it. This would require a detailed study which can best be done only by a technical study group. I propose, therefore, to appoint such a Group.

126. The proposals that I have presented will yield additional revenue of Rs. 465.41 crores in customs duties and Rs. 33.10 crores in excise duties. There would be a transfer of Rs. 43.64 crores from the basic duty account to the additional duty (in lieu of sales tax) account. The concessions and

reliefs aggregate Rs. 7.26 crores on the customs side and Rs. 222.43 crores on the excise side. The net yield from customs duties is Rs. 458.15 crores. The net loss from excise duties comes to Rs. 189.33 crores out of which Centre's share would be Rs. 148.95 crores and States' share would be Rs. 40.38 crores. This takes into account the States' share from additional excise duties in lieu of sales tax to the extent of Rs. 52.31 crores. The accrual to the central exchequer for the additional tax effort in a full year would be Rs. 309.20 crores.

127. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 1st March, 1984 will be laid on the Table of the House in due course.

128. I had earlier stated that the budgetary deficit at the existing rates of taxation would be Rs. 2035 crores. The tax measures proposed now, taken together with reliefs and concessions, are estimated to yield net additional revenue of Rs. 272.88 crores to the Centre. This leaves an uncovered deficit of Rs. 1762 crores. It has been my endeavour to keep the budgetary deficit to a relatively low figure and I am sure

the Hon'ble Members would agree that this order of deficit is appropriate to our circumstances. I hope that the low deficit, combined with my proposals for boosting production and lowering prices, will have a salutary effect on the inflationary psychology in the economy.

If I may, at this point, quote from Kautilya's Arthashastra :—

एवं कुर्यात्समूदयं वृद्धिं चायस्य दर्शयेत् ।  
हासं व्ययस्य च प्रपञ्चः साध्यच्य विपर्ययम्

129. Four years ago, my distinguished predecessor, while presenting the first Budget of the present Government, had expressed our firm resolve to repair the damage and restore the country's economy to the path of stability, growth and social justice. Mr. Speaker, we have kept that promise.

130. I commend this Budget to the House.

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

